● वर्ष-6
● अंक-04
रायपुर, बुधवार
12 अगस्त 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज–7 >> नक्सल मुक्त बस्तर में निकली ...

संसद में बिल पर रार

जेपीसी में भेजा जा सकता है एफसीआरए बिल

नईदिल्ली। मंगलवार को सूत्रों ने बताया कि सरकार एफसीआरए संशोधन विधेयक, 2026 को आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने पर विचार कर रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ बीजेडी समेत कुछ दल इसे संयुक्त समिति को भेजे जाने के पक्ष में हैं। विधेयक में स्वष्टक्र लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में संबंधित संगठन की संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के लिए एक अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है। विपक्ष का आरोप है कि इसके कुछ प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों और ईसाई गैर सरकारी संगठनों की वैध विदेशी फंडिंग को प्रभावित कर सकते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि कानून किसी धर्म विशेष को लक्षित नहीं करता।

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एफसीआरए बिल का मुद्दा कैसे उठा? राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों ने एफसीआरए बिल का मुद्दा उठाया। हालांकि, यह बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। इन दलों ने सरकार से पूछा कि एफसीआरए बिल पर सदन में चर्चा कब होगी। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि सही समय आने पर इस बारे में फैसला लिया जाएगा।

किन दलों ने बिल वापस लेने की मांग की?: कांग्रेस और एफसीआरए ने विधेयक

को वापस लेने की मांग की। वहीं, बीजेडी जैसे कुछ अन्य दलों का मानना है कि विधेयक को और गहन जांच-पड़ताल के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक, भी चाहती है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए।

एफसीआरएबिल लोकसभा में कब पेश किया गया था?: यह विधेयक इसी साल 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था। इसमें देश में गैर-सरकारी संगठनों और विदेशी फंडिंग पर सरकार की निगरानी और नियंत्रण को और मजबूत करने का प्रस्ताव किया गया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में बुधवार को लोकसभा में प्रस्ताव लाया जा सकता है।

एफसीआरए बिल में किस तरह की नई व्यवस्था का प्रस्ताव है?: इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसी अथॉरिटी का गठन करना है, जो किसी संगठन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होने की स्थिति में उसकी संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान की प्रक्रिया संभाल सके। एफसीआरए बिल का कड़ा विरोध कर रहे विपक्षी दलों का आरोप है कि इसके प्रावधान अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं। विपक्ष का कहना है कि विधेयक के कुछ प्रावधान ईसाई एनजीओएस और अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित सामाजिक कल्याण एवं शैक्षणिक संस्थानों के लिए मिलने वाली वैध विदेशी फंडिंग पर रोक लगा सकते हैं।

सरकार ने धार्मिक भेदभाव के आरोपों पर क्या कहा?: सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित कानून किसी धर्म विशेष को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। सरकार के मुताबिक, विधेयक का उद्देश्य देश में आने वाले विदेशी योगदान को विनियमित करना और उससे जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करना है।

राज्यसभा कीबीएसी बैठक में कौन-कौन शामिल हुए?: राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन सी. पी. राधाकृष्णन ने की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, सदन के नेता जे. पी. नड्डा और विपक्ष के नेता जयराम रमेश शामिल हुए। इनके अलावा तिरुचि शिवा और सस्मित पात्रा ने भी बैठक में हिस्सा लिया।

गश्ती पोत श्रुति लॉन्च

- NGOPV श्रुति को GRSE कोलकाता में लॉन्च किया गया।
- समुद्री निगरानी से सर्च-रेस्क्यू तक निभाएगा जिम्मेदारी।
- एंटी-पायरेसी और आपदा राहत मिशन में भी होगा इस्तेमाल।

नईदिल्ली। भारतीय नौसेना के बेड़े में एक और स्वदेशी पोत शामिल होने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नेक्स्ट जेनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल (एनजीओपीवी) श्रुति को मंगलवार को लॉन्च किया गया। अधिकारियों के मुताबिक, यह भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण अभियान की दिशा में एक और अहम उपलब्धि है। 'श्रुति' को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) में लॉन्च किया गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, यार्ड 3037 के नाम से निर्माणाधीन इस पोत के लॉन्च कार्यक्रम में वाइस एडमिरल संजय साधु, कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन मौजूद रहे।

नई पीढ़ी के ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल भारतीय नौसेना के मौजूदा पोतों की क्षमता बढ़ाएंगे। इन्हें कई तरह के समुद्री अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

इन जहाजों को देश में ही डिजाइन और तैयार किया जा रहा है। इससे भारतीय नौसेना की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

एनजीओपीवी का निर्माण एक साथ दो शिपयार्ड में किया जा रहा है। इनमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) और कोलकाता का गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को लॉन्च किया गया 'श्रुति' जीआरएसई में तैयार किया जा रहा पोत है। लॉन्च कार्यक्रम में भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय और जीआरएसई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन स्वदेशी पोतों के नाम भारत की समृद्ध विरासत से जुड़े हैं। नए पोत का नाम 'श्रुति' रखा गया है, जो चार वेदों का संदर्भ देता है। जहाज के क्रेस्ट में उर्सा मेजर तारामंडल और लाल-सफेद रंग का लाइटहाउस दर्शाया गया है। यह डिजाइन पोत की पहचान और उसकी भूमिका से जुड़े प्रतीकों को सामने रखता है।रक्षा मंत्रालय ने कहा कि श्रुति का लॉन्च भारतीय नौसेना के स्वदेशी जहाज निर्माण अभियान में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।

वंदे मातरम् बिल बना कानून राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को %वंदे मातरम बिल को मंजूरी दे दी, जिससे राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान के समान कानूनी संरक्षण मिल गया है। संसद ने पिछले महीने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 पास किया, जिसमें राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 में संशोधन किया गया। इस कानून का मकसद वंदे मातरम को भी राष्ट्रीय गान जन गण मनजैसी ही कानूनी सुरक्षा देना है।

राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। अब ऐसे अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सज़ा हो सकती है। इससे पहले, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गान (जन गण मन) को गाने से जानबूझकर रोकना या इसे गाते समय किसी सभा में बाधा डालना मना था। इन अपराधों के लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सज़ा का प्रावधान था, जबकि दूसरी बार और उसके बाद हर बार दोषी पाए जाने पर कम से कम एक साल की जेल की सज़ा होती थी। पुराने कानून में राष्ट्रीय गीत के लिए वैसी सुरक्षा नहीं थी। बिल में कहा गया है कि अभी वंदे मातरम के गायन के अपमान को रोकने के लिए कोई खास कानूनी प्रावधान नहीं है, जबकि इसे राष्ट्रीय गीत का सम्मान प्राप्त है। इसलिए, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय गीत गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में बाधा डालने से रोकने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करके राष्ट्रीय गीत को भी इसके दायरे में लाने का प्रस्ताव है, ताकि ऐसे कार्यों को दंडनीय बनाया जा सके।

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आज कांकेर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अप्रतिम उत्साह के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा की ढाई किमी पैदल रैली में जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, विद्यार्थी, अधिकारी-कर्मचारी और शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। विधायक श्री आशाराम नेताम और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने भी तिरंगा यात्रा में भागीदारी की।

प्रमुख समाचार

अमेरिका-ब्रिटेन-कनाडा के दौरे पर जाएंगे मोहन भागवत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत 25 अगस्त से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करेंगे। यह जानकारी सूत्रों के अनुसार है। डॉ. भागवत भारतीय प्रवासी समुदाय से जुड़े विभिन्न स्थानीय संघों और संगठनों के निमंत्रण

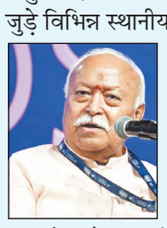

पर विदेश यात्रा करने वाले हैं। यह दौरा ऐसे अहम समय पर हो रहा है जब आरएसएस अपनी शताब्दी मना रहा है। अपने दौरे के दौरान, भागवत के भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों और स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने की उम्मीद है। उनकी यात्रा कार्यक्रम और व्यस्तताओं के बारे में आगे की जानकारी बाद में घोषित किए जाने की उम्मीद है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक पोस्ट में, आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा, आरएसएस के सरसंघचालक (प्रमुख) डॉ. मोहन भगवत विदेशों में स्थित स्थानीय संघों और संगठनों के निमंत्रण पर 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा आरएसएस के चल रहे शताब्दी वर्ष के अवसर पर हो रही है।

संसद में अमित शाह का सामना करें नेता प्रतिपक्ष : रिजिजू

नई दिल्ली। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अब जब गृह मंत्री अमित शाह उनके द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं तो राहुल गांधी को संसद से नहीं भागना चाहिए। किरेन रिजिजू की ये

टिप्पणी हालिया छात्र प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर हुए हंगामे के बीच आई है। इस मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र में जमकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा हुआ है। विपक्ष इस पर गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिक्रिया चाहता है और गृह मंत्री के संसद सत्र में शामिल नहीं होने पर सवाल उठा रहा है। किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी कई दिनों से अमित शाह से जवाब मांग रहे थे। अब जब गृह मंत्री हर मुद्दे का विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हैं तो उन्हें भागना नहीं चाहिए। इससे पहले सोमवार को राहुल गांधी ने कहा था कि विपक्ष अमित शाह की राय सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता है।

राहुल गांधी अपना रहे दोहरा रवैया : अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सांसदों ने मंगलवार को विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे संसद में चर्चा से भाग रहे हैं। वहीं, कांग्रेस सांसद प्रियंका

गांधी ने एनडीए के प्रदर्शन पर तंज कसा। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, झारखंड के युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। उन पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया और ज्यादतियां हुईं, उससे राहुल गांधी की सोच का पता चलता है। इससे साफ होता है कि उनके समर्थकों की सरकार वाले राज्य में युवाओं के साथ कैसा बुरा बर्ताव हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें न्याय से कैसे वंचित रखा जा रहा है। फिर भी, दूसरी तरफ, वे खुद तो सदन में आते नहीं, लेकिन गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं। गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए झूठ फैला रहे हैं और गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं।

ममता पर हमला लोकतंत्र पर सीधा आघातः शिवसेना यूबीटी

मुंबई। शिवसेना यूबीटी ने मंगलवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर हुआ हमला केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक हस्ती पर हमला नहीं है, बल्कि यह हमारे गणतंत्र के लोकतांत्रिक ताने-बाने पर सीधा प्रहार है। पार्टी ने

अपने मुखपत्र सामना में कहा, पत्थरों, लाठियों और लोहे की छड़ों से लैस एक भीड़ ने उनके वाहन को घेर लिया, जिसका साफ उद्देश्य एक सशक्त विपक्षी आवाज को खत्म करना लग रहा था। उनका बच जाना सिर्फ संयोग की बात है, लेकिन इस घटना से एक भयावह सच्चाई सामने आती है, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की स्थिति सभी सीमाओं को पार कर चुकी है। सामना के संपादकीय में कहा गया है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि जहां केंद्रीय नेतृत्व दलबदलुओं का गर्मजोशी से स्वागत करता है, वहीं राज्य में राजनीतिक आधार तैयार करने वाले नेता जानलेवा हमलों के शिकार हो रहे हैं।

ओम बिरला ने संसद में कामकाज के लिए विपक्ष से की अपील

नईदिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को सदन से सामान्य कामकाज फिर से शुरू करने की पुरज़ोर अपील की। उन्होंने बताया कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने और गृह मंत्री की ओर से जवाब देने के लिए सहमत हो गई है। साथ ही, उन्होंने सदन में लगातार हो रहे व्यवधान पर अपनी

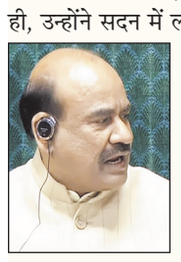

व्यक्तिगत निराशा भी ज़ाहिर की। गतिरोध के बीच सदस्यों को संबोधित करते हुए स्पीकर बिरला ने प्रश्न काल के महत्व पर ज़ोर दिया। बिरला ने कहा कि सदस्यगण, मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया है कि प्रश्न काल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। प्रश्न काल के दौरान ही सरकार की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। कई माननीय सदस्यों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर आग्रह किया है। मैंने पहले ही व्यवस्था दी है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, प्रश्न काल के दौरान केवल प्रश्न काल की ही कार्यवाही होगी। इसलिए, कृपया प्रश्न काल के संचालन में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि जनता संसद से सार्थक कामकाज की उम्मीद करती है।

ढाका में रहमान, दिल्ली में मोदी; पटरी पर लौट रहे भारत-बांग्लादेश के रिश्ते?

प्रशांत तिवारी

भारत और बांग्लादेश के बीच हालिया कूटनीतिक तनाव के बीच दोनों देशों के रिश्तों को सामान्य और मजबूत बनाने के संकेत मिल रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन मांगा। इससे एक दिन पहले उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की थी। दोनों बैठकों में आपसी हितों, जन-केंद्रित सहयोग और संबंधों को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। विशेषज्ञ इसे दोनों देशों के बीच रिश्तों में संभावित सुधार के संकेत के तौर पर देख रहे हैं।

पीएम मोदी से मुलाकात में क्या संदेश दिया गया?

बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और लोगों को केंद्र में रखते हुए रचनात्मक तरीके से भारत और बांग्लादेश के बीच बहुआयामी और स्थायी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनका मार्गदर्शन मांगा।

सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के साथ बैठक के दौरान उच्चायुक्त त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार और वहां के लोगों के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्योन्मुखी तरीके से मिलकर काम करने की भारत की इच्छा भी जताई। बैठक के बाद बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा, %उन्होंने आपसी हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और लोगों को केंद्र में रखते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक तनाव के बाद एक सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच हुई सौहार्दपूर्ण बातचीत से संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष हालिया मतभेदों को पीछे छोड़कर भारत-बांग्लादेश संबंधों के व्यापक हितों पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं।

बांग्लादेश के डेली सन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश-भारत

संबंधों में हालिया तनाव दोनों सरकारों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, लेकिन इसे खुद पैदा किया गया संकट नहीं बनने देना चाहिए। भूगोल, इतिहास, व्यापार, नदियां, सुरक्षा और लोगों के बीच गहरे संबंध इन दोनों पड़ोसियों को इस तरह जोड़ते हैं, जिन्हें कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। राजनीतिक असहमति अपरिहार्य है; उन्हें व्यापक संबंधों पर हावी होने देना एक विकल्प है। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ढाका और दिल्ली दोनों ही इस बात की आवश्यकता को समझते हैं कि ऐसा होने से रोका जाए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हालिया बातचीत ने ढाका में तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की थीं। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि हसीना की हालिया वर्चुअल मीडिया बातचीत में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस कार्यक्रम में की गई किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता, खासकर उन टिप्पणियों का जो ढाका में विधिवत गठित सरकार से संबंधित थीं।

रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि पद संभालने के बाद से ही भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने सुलह और संवाद पर जोर देने वाला रुख अपनाया है। उन्होंने आपसी समझ के जरिए दोनों देशों के बीच मौजूद चुनौतियों को सुलझाने की जरूरत पर बल दिया है और भारत-बांग्लादेश संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर उम्मीद भी जताई है।रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बांग्लादेश और भारत अतीत में एक जैसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। दोनों देशों के इतिहास में मुश्किल द्विपक्षीय विवादों के साथ-साथ सफल कूटनीति के उदाहरण भी मौजूद हैं।डेली सन की रिपोर्ट में कहा गया, इसके लिए दोनों तरफ से धैर्य, बातचीत और राजनीतिक साहस की जरूरत थी। एक ऐसी समस्या, जो कई सरकारों के कार्यकाल से चली आ रही थी, इसलिए सुलझाई जा सकी क्योंकि आखिरकार दोनों देशों ने तय किया कि मौजूदा असंतोषजनक स्थिति को लंबे समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता। इससे एक स्पष्ट सबक मिलता है- मुश्किल मुद्दों को यूं ही छोड़ देने से वे शायद ही कभी सुलझते हैं।%

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण, जिसमें सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी शामिल है, दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत का एक और संभावित जरिया बन सकता है।

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

नया छत्तीसगढ़, नया भारत

नवा रायपुर अटल नगर

भारत के स्मार्ट शहरों में उभरता नया सितारा

योजनाबद्ध अधोसंरचना, आधुनिक सुविधाऐं और सतत विकास के साथ नवा रायपुर अटल नगर भविष्य के भारत का आदर्श शहरी मॉडल बन रहा है।

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

नवा रायपुर अटल नगर की एक झलक

छत्तीसगढ़ की आधुनिक और योजनाबद्ध राजधानी नवा रायपुर अटल नगर आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे स्मार्ट शहरों में शामिल है। सुव्यवस्थित अधोसंरचना, हरित विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, पर्यटन और महिला सशक्तीकरण जैसे विविध क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति ने नवा रायपुर को भविष्य के भारत का आदर्श शहरी मॉडल बना दिया है। यह केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि निवेश, नवाचार और समावेशी विकास का उभरता हुआ केंद्र है।

स्मार्ट अधोसंरचना और शहरी सेवाओं में बड़ी उपलब्धियों

- 52 एमपलडी क्षमता की पाइपलाइन और अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र के माध्यम से पूरे शहर में दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित।
- 10.66 किलोमीटर लंबी बायोस्वेल्स, रिचार्ज पिट्स और प्राकृतिक जल निकासी तंत्र का विकास।
- वर्षाजल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा, पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ किया।

परिवहन और कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम

- **रायपुर – राजिम** रेल सेवा का नवा रायपुर के सीबीडी स्टेशन तक विस्तार ।
- महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही और स्वरोजगार के लिए पिंक ई-रिक्शा सेवा शुरू।
- ई - बस संचालन हेतु चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार, सेवा प्रारंभ होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में।
- हरित और टिकाऊ शहरी परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण।

शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो रहा एडुसिटी

- 13 सहकारी विद्यालयों का उन्नयन और 2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित ।
- लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में एडुसिटी का विकास।
- NIFT, NIELIT NFSU, नरसी मोन्जी ग्रुप इंस्टीट्यूशंस को भूमि आवंटित।
- सेक्टर-7 में 17 एकड़ भूमि पर आवासीय विद्यालय की स्थापना प्रस्तावित।

मेडिसिटी : स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र

- लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में विश्वस्तरीय मेडिसिटी का विकास।
- सुपर स्पेशिवलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डायनोस्टिक सेंटर, धर्मशाला, होटल एवं आवासीय सुविधाऐं।
- Bombay Hospital को 300 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशिवलिटी हॉस्पिटल हेतु भूमि आवंटित ।
- लगभग 50 एकड़ भूमि आवासीय विकास हेतु आवंटित, लगभग 350 करोड़ रूपये के निवेश की संभावना।

महिला सशक्तीकरण और श्रमिक कल्याण

- कार्यरत महिलाओं के लिए 1,000 क्षमता वाले वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण, 109 करोड़ रूपये की लागत से।
- प्रवासी श्रमिकों के लिए 1,100 क्षमता वाला सुरसुविधायुक्त श्रमिक आवास भवन 40 करोड़ रूपये की लागत से तैयार किया जा रहा है।

पर्यटन, संस्कृति और MICE गंतव्य के रूप में उभार

- 77 एकड़ में सेवाग्राम तथा सेक्टर-39 में आर्ट ऑफ़ लिविंग फाउंडेशन को 40 एकड़ भूमि आवंटित ।
- सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के बड़े केंद्र विकसित हो रहे है।
- सेक्टर-4 और 10 में लगभग 120 एकड़ क्षेत्र में निजी निवेश से कन्वेंशन सेंटर कम स्पोर्ट्स सिटी का विकास।
- लगभग 800 करोड़ रूपये की परियोजना में विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर एवं खेल सुविधाएँ शामिल ।

सेमीकंडकटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का उभरता हब

- राज्य का पहला SEZ आधारित एआई डेटा सेंटर पार्क, लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निजी निवेश।
- भारत का पहला GaN तकनीक आधारित सेमिकंडकटर प्लांट स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित।
- इलेक्ट्रॉनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) हेतु भारत सरकार से स्वीकृति । PCB प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग, EMC टेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ।
- सीबीडी क्षेत्र में प्लग-एंड-प्ये मॉडल पर आईटी कंपनियों को सुसजित कार्यालय स्थान ।
- वर्तमान में लगभग 1,000 युवा कार्यरत 2,000 अतिरिक्त रोजगार की संभावना ।

सतत विकास और हरित पहल

- पीपल फॉर पीपल अभियान अंतर्गत 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।
- शहर के 26 प्रतिशत हरित क्षेत्र को संरक्षित और विस्तारित करने में मदद मिली।
- बायोस्वेल्स, रिचार्ज सिस्टम और हरित कॉरिडोर जैसे उपायों से नवा रायपुर पर्यावरण अनुकूल और जल-संवेदनशील शहर के रूप में स्थापित ।

प्राधिकरण की आगामी कार्ययोजना

- सेरीखेड़ी और मंदिर हसौद क्षेत्र में लगभग 1,100 एकड़ पर 800 करोड़ रूपये की लागत से अधोसंरचना विकास।
- राज्य राजधानी क्षेत्र (SCR) के एकीकृत विकास हेतु विशेष प्राधिकरण गठन ।
- 500 एकड़ में मेडिसिटी और 200 एकड़ में एडलिटी का विस्तार ।
- नवा रायपुर को IT. ITeS और AI हब के रूप में स्थारित करना ।
- वार्षिक पूँजीगत व्यय क्षमता को 1,000 करोड़ रूपये तक बढ़ाना।
- वेलनेस सेंटर, वेडिंग डेस्टिनेशन, MICE कैपिटल और पर्यटन परियोजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन ।
- प्रभावित ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास योजना के आधार पर आधुनिक अधोसंरचना विकास।
- इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) का तकनीकी उन्नयन।
- सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने हेतु 40 नई ई-बसों का संचालन।

योजनाबद्ध विकास, आधुनिक सुविधाएं और सतत शहरीकरण के साथ
नवा रायपुर अटल नगर - नए भारत की नई पहचान, नई उड़ान

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ शासन

NAVA RAIPUR ATAL NAGAR

संवाद-48628/1

संक्षिप्त समाचार

हरेली पर नवा रायपुर में सजेगी लोक संस्कृति की महफिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू और लोक-परंपरा के प्रतीक पर्व 'हरेली' के अवसर पर नवा रायपुर में एक भव्य और गरिमामय आयोजन होने जा रहा है। राजस्व, आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा द्वारा आयोजित इस विशेष 'हरेली अऊ गृह प्रवेश' कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित शासन और संगठन का शीर्ष नेतृत्व शिरकत करेगा। बुधवार 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक नवा रायपुर के सेक्टर 24 के एम-12 स्थित आवास परिसर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम देखने को मिलेगा। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव व विजय शर्मा, रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल की गरिमामयी मौजूदगी रहेगी। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व का विशेष धार्मिक और कृषि महत्व है। इस दिन किसान अपने हल-नागर और कृषि औजारों की पूजा कर अच्छी फसल व राज्य की सुख- समृद्धि की कामना करते हैं। गृह प्रवेश और हरेली के इस दोहरे शुभ अवसर पर मंत्री टंक राम वर्मा ने प्रदेशवासियों और शुभचिंतकों को सहर्ष 'नेवता' (निमंत्रण) भेजकर पारंपरिक छत्तीसगढ़ी पकवानों और लोक-संस्कृति के इस उल्लास में शामिल होने का आग्रह किया है।

मिनीमाता जी की पुण्यतिथि पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया सादर नमन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने नारी सशक्तिकरण की प्रखर आवाज और छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनीमाता जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मिनीमाता जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए समर्पित किया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाते हुए महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद के रूप में मिनीमाता जी का सार्वजनिक जीवन प्रदेश की महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका संघर्ष, सेवा और जनकल्याण के प्रति समर्पण आज भी समाज को नई दिशा प्रदान करता है। श्री ओपी चौधरी ने कहा कि मिनीमाता जी के आदर्शों और विचारों को आत्मसात करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक न्याय, समानता और नारी सम्मान के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा।

स्वतंत्रता दिवस : इंद्रावती भवन में आईएएस अवनीश शरण करेंगे ध्वजारोहण

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन प्रांगण में ध्वजारोहण कार्यक्रम संबंधी परिपत्र जारी किया है। जारी निर्देशानुसार, 15 अगस्त 2026 को प्रातः 8:00 बजे नगर तथा ग्राम निवेश के आयुक्त एवं गृह निर्माण मंडल के अतिरिक्त प्रभार आयुक्त श्री अवनीश कुमार शरण द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समारोह में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया है।

'हर घर तिरंगा' अभियानः खिलाड़ियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों ने लिया हिस्सा

रायपुर। 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत बिलासपुर के बहतराई स्थित खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में सेंटर के खिलाड़ियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। हाथों में तिरंगा लेकर निकले खिलाड़ियों ने देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के उत्साह से सराबोर नजर आया। खिलाड़ियों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ तिरंगा लहराते हुए राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना व्यक्त की। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी अभियान के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने और नागरिकों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित इस आयोजन का उद्देश्य खिलाड़ियों और युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना को और मजबूत करना तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना जागृत करना था। आयोजन के माध्यम से 'हर घर तिरंगा' अभियान के संदेश को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया।

राखी से पहले मिला विष्णु भैया का उपहार, महिलाओं के चेहरों पर बिखरी मुस्कान

रायपुर। रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट स्नेह, विश्वास और सुरक्षा के वादे का प्रतीक है। इस पावन पर्व से ठीक पहले विष्णु भैय्या की छत्तीसगढ़ सरकार 'महतारी वंदन योजना' ने जिले की हज़ारों महिलाओं के जीवन में स्वाभिमान और आर्थिक आत्मनिर्भरता की नई मिठास घोल दी है। योजना के तहत सीधे बैंक खातों में पहुंची राशि बहनों के लिए केवल एक आर्थिक मदद नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए अपने सामर्थ्य से त्योहार की खुशियां मनाने का सशक्त माध्यम बन गई है। धमतरी जिले की मुजगहन निवासी मंजू यादव, धमतरी की शिवानी साहू और पोटियाडीह की मीनाक्षी निर्मलकर के लिए यह योजना उनके आत्मसम्मान का संबल बनी है। मुजगहन की मंजू यादव चेहरे पर बिखरी खुशी के साथ बताती हैं कि इस बार विष्णु भैय्या के भेजे पैसे से रक्षाबंधन पर अपने लिए नई साड़ी खरीदूंगी। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि से अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

देशभक्ति से ओतप्रोत अप्रतिम उत्साह के साथ निकली तिरंगा यात्रा

■ उप मुख्यमंत्री अरुण साव हुए शामिल

रायपुर। उप मुख्यमंत्री तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आज कांकेर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। अप्रतिम उत्साह के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा की ढाई किमी पैदल रैली में जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, विद्यार्थी, अधिकारी-कर्मचारी और शहरवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। विधायक श्री आशाराम नेताम और छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत ने भी तिरंगा यात्रा में भागीदारी की।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में शासकीय नरहरदेव उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के खेल मैदान से शुरू हुई तिरंगा यात्रा नगर घड़ी चौक, ऊपर-नीचे रोड, मस्जिद चौक, गांधी चौक होते हुए नवनिर्मित मिनी स्टेडियम परिसर में सम्पन्न हुई। इसमें बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों-कर्मचारियों, गणमान्य नागरिकों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारियों ने हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर उत्साह से भाग लिया।

यात्रा की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन से की गई। नागरिकों ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर रैली में शामिल लोगों का स्वागत किया तथा देशभक्ति के नारे लगाए। नगरवासियों ने चॉकलेट व टॉफी बांटकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के निर्देश पर वंदेमातरम् गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर इस जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। तिरंगा यात्रा में शामिल विद्यार्थियों ने 92 फीट लंबा तथा 5 फीट चौड़ा तिरंगा का प्रदर्शन किया। शहर के विभिन्न मार्गों और चौक-चौराहों पर इसे लहराते हुए यात्रा निकाली गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। सेंट माइकल इंग्लिश स्कूल की बैंड टोली में शामिल छात्राओं ने राष्ट्रगीत की धुन पर वाद्य यंत्र बजाते हुए रैली में मार्चपास्ट किया।

केंद्र शासन एवं राज्य शासन के निर्देश पर 9 अगस्त से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने एवं राष्ट्रीय गीत वंदेमातरम के गायन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे लोगों में देश भक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो।

कांकेर नगर पालिका के अध्यक्ष श्री अरुण कौशिक, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी, कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, एसपी श्री निखिल राखेचा, श्री महेश जैन, श्री सतीश लाटिया, श्री राहुल टिकरिहा, श्री राजा देवनानी, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती तारा ठाकुर, कांकेर नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री उत्तम यादव, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले, जिला पंचायत के सीईओ श्री हरेश मंडावी और जिला शिक्षा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी श्री रमेश निषाद भी तिरंगा यात्रा में मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ में व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं

रायपुर। पूर्वोत्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिटी, दिल्ली-एनसीआर तथा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को समन्वयक श्री सुशील अग्रवाल के नेतृत्व में राज्यपाल श्री रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। इस दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर तथा दिल्ली-एनसीआर के बीच व्यापारिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है और यहां वनोपज, कृषि एवं फार्मिंग, स्टील, चाय सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार एवं उद्योग की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं एवं हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए भी पूर्वोत्तर राज्यों तथा दिल्ली-एनसीआर में व्यापार एवं उद्योग के विस्तार की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। उन्होंने दोनों क्षेत्रों के चैंबर ऑफ कॉमर्स से आपसी समन्वय बढ़ाकर व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडलों ने आपसी व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने तथा व्यापार एवं उद्योग के नए अवसर विकसित करने के संबंध में अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर पूर्वोत्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड कम्युनिटी, नई दिल्ली-एनसीआर के अध्यक्ष श्री अजय खेमानी, श्री राजेश सोनी, सह-समन्वयक श्री सारंग अग्रवाल तथा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री सतीश थोरानी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

झीरम कांड में अंतिम सुनवाईः अजय चंद्राकर का कांग्रेस पर हमला

■ कहा- इनको सच्चाई नहीं चाहिए, खुद जज बनकर राजीव भवन से सुना दें फैसला

रायपुर। झीरम घाटी मामले की एनआईए स्पेशल कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर कांग्रेस के बयानों पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता खुद ही जज बन जाएं और कांग्रेस भवन से ही फैसला सुना दें। विधायक चंद्राकर ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है और वह केवल झीरम मामले पर राजनीति करना चाहती है।

भाजपा सरकार और संगठन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस नहीं मनाने और बधाई तक नहीं देने को कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया। आज 15 जिलों में कांग्रेस इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि विश्व के मूल निवासियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को होता है और कांग्रेस को इस प्रस्ताव को पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अक्ल की कमी है और भाजपा को कांग्रेस से मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि उसने आदिवासियों के लिए क्या किया है।

कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बयान दिया कि महिलाओं की राजनीति में भाजपा के नेता सबसे ज्यादा दखल देते हैं। इस पर विधायक चंद्राकर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद महिला और महिला पुत्र के इर्द-गिर्द चल रही है। पूरी पार्टी में महिला और उनके पुत्र का ही दखल है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये 'हाइब्रिड नस्ल' के हैं, देसी नस्ल के भी नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ में 'पार्षद पति' व्यवस्था खत्म करने संबंधी सरकार के राजपत्र जारी होने पर अजय चंद्राकर ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और गैर-राजनीतिक विवादों से ऊपर उठकर इस व्यवस्था पर काम किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि नगरीय निकायों में 33 प्रतिशत और पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए है।

जल-पर्यावरण संरक्षण और आजीविका का सशक्त माध्यम : टंक राम वर्मा

■ राजस्व मंत्री ने छुहीपाली में किया सीड बॉल का बीजारोपण

रायपुर। सीड बॉल अभियान एक पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण की तकनीक है। इसमें मिट्टी, खाद और बीजों को मिलाकर छोटी-छोटी गोलियां (सीड बॉल) बनाई जाती हैं। इन्हें सूखने के बाद खाली और दुर्गम जमीनों या पहाड़ियों पर फेंक दिया जाता है। बारिश का पानी मिलने पर मिट्टी गल जाती है और बीज स्वतः अंकुरित होकर पौधा बन जाते हैं द्य

जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सीड बॉल अभियान को उस वक्त और बल मिला, जब राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने स्वयं धरातल पर उतरकर इसमें सहभागिता निभाई। उन्होंने सारंगढ़-बिलाईगढ जिले के सारंगढ़ ब्लॉक के ग्राम छुहीपाली स्थित पठारी क्षेत्र में 5 हजार सीड बॉल का वृहद बीजारोपण किया तथा नवनिर्मित डबरी की मेड़ पर 30 पौधों का रोपण किया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वीबीजीरामजी योजना और बिहान समूह की महिलाओं के विशेष उत्साह के बीच आयोजित इस वृहद कार्यक्रम में सैकड़ों ग्रामीणों सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि पर्यावरण को सहेजना और भू-जल स्तर को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। छुहीपाली के इस पहाड़ी क्षेत्र में सीड बॉल बीजारोपण और स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण न केवल मृदा और जल संरक्षण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, बल्कि इससे बारिश के मौसम में ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। हमारी सरकार जन-कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने और पर्यावरण संवर्धन के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री वर्मा ने स्थानीय महिलाओं से संवाद कर महतारी वंदन योजना की राशि के नियमित भुगतान की जानकारी ली, जिस पर महिलाओं ने खुशी जताते हुए सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों से उनके नाम, शिक्षा और क्षेत्र में उपलब्ध स्कूली सुविधाओं के संबंध में भी आत्मीय बातचीत की।

ग्राम पंचायत छुहीपाली के दो हेक्टेयर पहाड़ी ढलान क्षेत्र में 5.60 लाख रुपये की लागत से स्टैगर्ड कंटूर ट्रेंच का निर्माण कराया जा रहा है। अब तक निर्मित 2,400 ट्रेंचों के माध्यम से पहाड़ से बहने वाले जल की गति को रोककर भूमिगत जलस्तर को बढ़ाया जाएगा और मिट्टी के कटाव को रोका जाएगा। इसके अतिरिक्त, पहाड़ी जल को सहेजने के लिए एक नए तालाब का निर्माण भी पूर्ण किया गया है, जो क्षेत्र में जल संकट को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,पूर्व विधायक श्रीमती केराबाई मनहर,कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक सहित बिहान की महिला सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे।

शराब घोटाला केस में कांग्रेस नेता गिरफ्तार

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कथित 3400 करोड़ रुपये के शराब घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की कार्रवाई के बाद अब उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किए जाने की तैयारी है। कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी मामले से जुड़े तथ्यों और लेन-देन की जांच के लिए रिमांड की मांग कर सकती है। रामगोपाल अग्रवाल का नाम लंबे समय से छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले की जांच से जुड़ा रहा है। जांच एजेंसियां कथित शराब घोटाले में वित्तीय लेन-देन, नेटवर्क और इससे जुड़े लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं। ईडी अब अग्रवाल से भी इन्हीं पहलुओं को लेकर पूछताछ कर सकती है। गिरफ्तारी से पहले रामगोपाल अग्रवाल ने पिछले महीने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो के कार्यालय में सरेंडर किया था। इसके बाद मामले में उनकी भूमिका को लेकर जांच आगे बढ़ी। अब ईडी की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा और बढ़ गया है। रामगोपाल अग्रवाल पहले भी केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई के घेरे में आ चुके हैं। वर्ष 2023 में श्वष्ठ ने उनसे जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। उस समय भी कथित शराब घोटाले को लेकर प्रदेश की राजनीति में काफी हलचल देखने को मिली थी। छापेमारी के बाद से ही अग्रवाल का नाम इस मामले की जांच से जुड़ा रहा। अब उनकी गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाला प्रकरण एक बार फिर चर्चा में है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस भर्ती मुख्य परीक्षा की तिथियों में बदलाव

■ अब सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग एवं प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा 02, 03 एवं 04 नवम्बर को होगी

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के युवाओं के हित में संवेदनशील निर्णय लेते हुए शिक्षक भर्ती परीक्षा और सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर मुख्य परीक्षा की तिथियां एक साथ होने से अभ्यर्थियों को हो रही परेशानी का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को परीक्षा तिथियों में आवश्यक बदलाव के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर (मुख्य) परीक्षा-2024 की संशोधित तिथियां घोषित कर दी हैं।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा गृह (पुलिस) विभाग के अंतर्गत सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर परीक्षा-2024 की प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम 04 अगस्त 2026 को जारी किया गया था। इसके साथ मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए 24, 25 एवं 26 अक्टूबर 2026 की संभावित तिथियां निर्धारित की गई थीं। इसी दौरान 25 अक्टूबर 2026 को शिक्षक भर्ती परीक्षा भी आयोजित होने के कारण दोनों परीक्षाओं की तिथियों में टकराव की स्थिति बन गई थी। इससे दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के सामने किसी एक परीक्षा से वंचित होने की आशंका उत्पन्न हो गई थी।

अभ्यर्थियों की इस व्यावहारिक समस्या की जानकारी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के संज्ञान में आने पर उन्होंने तत्काल अधिकारियों को युवाओं के हित में समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा की पूर्व निर्धारित तिथियों में परिवर्तन किया गया है। अब सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमांडर (मुख्य) परीक्षा-2024 का आयोजन 02, 03 एवं 04 नवम्बर 2026 को किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवाओं का हित हमारी सरकार के लिए सर्वोपरि है। प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का हर अवसर मिले और केवल परीक्षा तिथियों के टकराव के कारण कोई भी पात्र अभ्यर्थी अवसर से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवा वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं। ऐसे में प्रशासनिक अथवा परीक्षा कार्यक्रम से जुड़ी किसी व्यावहारिक समस्या के कारण उनके सामने दो अवसरों में से किसी एक को चुनने की विवशता नहीं होनी चाहिए।

मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक ली

रायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने मंगलवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार साधक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की।

मुख्य सचिव ने कहा है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण उनके सेवा निवृत्त होने से पहले ही तैयार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची विभागावार नियतकालिक अवधि में बनायी जाए।

विभागों में रिक्त पदों की सूची एवं बैकलॉक के पदों पर सेटअप बनाकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करें। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सेवा सेतु, लोक सेवा गारंटी, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी रेगुलेशन, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। बैठक में बताया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 728 सेवाएं को नोटिफाइड हो चूकी है।

मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाये। अधिकारी-कर्मचारियों को आई-गॉट के तहत विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने कहा है। अधिकारी- कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण के कार्ययोजना बनायें। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि रिफार्म के तहत अपने-अपने विभागवार जानकारी तैयार करें। आगामी दिनों में रिफार्म उत्सव अभियान का आयोजन होगा।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, विधि एवं विधायी विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती सुषमा सावंत, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमख सचिव श्रीमती शहला निगार, वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री एवं सुशासन अभिसरण विभाग के सचिव श्री राहुल भगत, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, खाद्य विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया, ऊर्जा विभाग के सचिव श्री सारांश मित्तर, श्रम विभाग के सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव श्री रजत कुमार, परिवहन विभाग के सचिव श्री एस.प्रकाश, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव श्री बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव सहित राज्य शासन के अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग-तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

// विज्ञापन //

क्रमांक/301/ /वा.3/अवि.अ./खाद्य/2026 अनुविभाग,तिल्दा-नेवरा, दिनांक :- 6/8/26

सर्व साधारण आम जनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुविभाग तिल्दा-नेवरा, में संचालित में शा.उ. मूल्य दुकानों की संचालन एजेंसी परिवर्तन किये जाने के फलस्वरुप लोक सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की खण्ड 09 के प्रावधान अनुसार निम्नलिखित शा.उ.मू. दुकान आबंटित करने हेतु इच्छुक सहकारी सोसाईटियों / महिला स्व-सहायता संमूह/ग्राम पंचायत विज्ञापन प्रकाशित दिनांक से 15 दिवस तक कार्यालयीन समयावधि में अपना आवेदन पत्र का विहित प्रारुप (परिशिष्ट-1), समूह/समिति को प्रस्ताव, पंजीयन प्रमाण पत्र, बैंक बचत खाता की छायाप्रति, ग्रेडिंग एवं अन्य सम्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) तिल्दा-नेवरा में जमा कर सकते है। नवीन संचालक की नियुक्ति हेतु विज्ञापित शा.उ.मू. दुकानों का विवरण इस प्रकार है :-

क्रमांक	ग्राम पंचायत का नाम	शा.उ.मू. दुकान क्रमांक
1	मोहदी	442004060

निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
तिल्दा-नेवरा
जिला रायपुर (छ.ग.)

जी-262702681/10

आखिर लोकतंत्र में गतिरोध कब तक?

हिमांशु सिंह चंदेल

पूरे मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों का सबसे बड़ा नुकसान संसद की कार्यवाही को हुआ है। संसद देश का वह मंच है, जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठते हैं, सरकार जवाब देती है और कानूनों पर चर्चा होती है। लेकिन लगातार हंगामे और गतिरोध के कारण इस काम में बाधा आई है। जिन सदनों में हर दिन औसतन सात घंटे काम होने की अपेक्षा रहती है, वहां कार्यवाही कई बार करीब एक घंटे तक ही सिमट गई। यह स्थिति किसी एक दल की जीत या हार नहीं, बल्कि पूरे संसदीय तंत्र के लिए चिंता का विषय है। विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब देने पर सहमति जताई है। यह कदम संसद में बने गतिरोध को खत्म करने की दिशा में एक शुरुआत हो सकता है। विपक्ष सवाल पूछता है और सरकार से जवाब मांगता है, यह संसदीय लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए अगर सरकार गृह मंत्री के जरिए इस मुद्दे पर सदन में जवाब देने को तैयार है, तो विपक्ष के सामने भी यह अवसर है कि वह संवाद के रास्ते को आगे बढ़ाए। संसद की कार्यवाही का बार-बार रुकना केवल सदन के भीतर का घटनाक्रम नहीं है। दोनों सदनों की कार्यवाही अब तक 88 बार स्थगित हो चुकी है। इसका मतलब है कि संसद के पास उपलब्ध समय का बड़ा हिस्सा कामकाज के बजाय व्यवधान में चला गया। संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है। इस समय का इस्तेमाल कानून बनाने, जनता की समस्याओं पर चर्चा करने और सरकार से जवाब मांगने में होना चाहिए। हंगामे के कारण जब कार्यवाही रुकती है, तो उसका असर सीधे उस जनता पर पड़ता है, जिसके नाम पर सांसद सदन में पहुंचते हैं। इस पूरे विवाद का एक गंभीर पहलू उन विधेयकों को लेकर भी है, जिन्हें लोकसभा में पर्याप्त चर्चा के बिना पारित कराया गया है। कानून बनाना जरूरी है, लेकिन कानून के हर प्रावधान को समझना और उसके संभावित असर पर चर्चा करना भी उतना ही जरूरी है। किसी विधेयक से समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, उसे लागू करने में क्या दिक्कतें आएंगी और उससे जुड़े सांविधानिक सवाल क्या हैं, इन मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। यही वह एकमात्र पैराग्राफ है, जहां बातों को बिंदुवार समझा जा सकता है। विधेयक का असर, सामाजिक-आर्थिक परिणाम, क्रियान्वयन की दिक्कतें और सांविधानिक सवाल। संसद में गतिरोध की जिम्मेदारी केवल सरकार या केवल विपक्ष पर डालकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना और उसकी नीतियों की जांच करना है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी सवालों का जवाब देना और सदन को चलाने के लिए जरूरी सहमति बनाना है। बार-बार सदन रोकना कुछ समय के लिए राजनीतिक मुद्दा जरूर बन सकता है, लेकिन इससे संसदीय गरिमा मजबूत नहीं होती। इसी तरह महत्वपूर्ण विधेयकों को संसदीय समितियों के पास भेजने की परंपरा को मजबूत करना भी जरूरी है, ताकि कानून बनने से पहले उनका पर्याप्त परीक्षण हो सके। गृह मंत्री का सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत की शुरुआत बन सकता है। अब जरूरत इस बात की है कि दोनों पक्ष इस मौके को व्यापक संवाद में बदलें। संसद में विपक्ष सवाल पूछे, सरकार जवाब दे और विधेयकों पर गंभीर चर्चा हो, यही संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी भावना है। हंगामे से किसी दल को तत्काल राजनीतिक फायदा दिखाई दे सकता है, लेकिन लंबे समय में इसकी कीमत संसद और जनता दोनों को चुकानी पड़ती है।

आरएसएस नेतृत्व के रुख में व्यावहारिक बदलाव के संकेत

शेखर गुप्ता

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख या सरसंघचालक मोहन भागवत ने संघ की शताब्दी की तैयारी के दौरान संगठन को नए सिरे से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में अपनी छवि में भारी बदलाव किया है। वह हमें यह तो नहीं बताएंगे कि यह बदलाव उन्हें रातों को करवटें बदलने पर विवश करता है या अच्छी नींद देता है। यह जरूर है कि चुनिंदा लोगों के लिए उदारवादी प्रतीक बन जाना उनके या किसी अन्य सरसंघचालक के केआरए (प्रमुख दायित्व क्षेत्र) में नहीं था।

इससे उनके वफादार और आलोचक दोनों भ्रमित हो गए। कट्टर वैचारिक आधार इस बात से विचलित है कि वह कुछ अधिक ही उदारवादी रुख अपना रहे हैं। इससे भारत में एक ऐसा पारंपरिक समूह उभर आया है जो पुराने हिंदू रूढ़िवाद और राष्ट्रवाद से जुड़ा रहना चाहता है जबकि उन्हें लगता है कि भागवत के नेतृत्व में आरएसएस उससे दूर जा रहा है।

उन्होंने कट्टर उदारवादी समुदाय को भी उलझन में डाल दिया है जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), नरेंद्र मोदी और आरएसएस एक ही हैं। उनमें से कुछ के लिए अब भागवत राहत लेकर आते हैं। क्या यह परिवर्तन की हवा है? क्या वह मोदी सरकार को चेतावनी दे रहे हैं? क्या वह आरएसएस की विश्वदृष्टि को केंद्र के करीब ला रहे हैं?

सबसे पहले यह रेखांकित करना जरूरी है कि आरएसएस की मूल विचारधारा और दर्शन बदलने वाला नहीं है। जो नजर आ रहा है वह है सत्ता के 13वें वर्ष में राजनीतिक व्यावहारिकता। बीते पांच साल में भागवत ने कई प्रमुख और विभाजनकारी मुद्दों पर संघ के रुख को बदला है या अलग व्याख्या की है। वह कई बार कह चुके हैं कि भारत में हर व्यक्ति का डीएनए 40,000 साल पहले से एक समान है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस धर्म का पालन करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग की तलाश बंद करनी चाहिए।

उन्होंने और उनके संभावित उत्तराधिकारी दत्तात्रेय होसबाले ने भी कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ जुड़े रहना चाहिए। वे इसे जनता से जनता के संपर्क के रूप में पेश कर सकते हैं लेकिन यही वे बदलाव हैं जिनसे

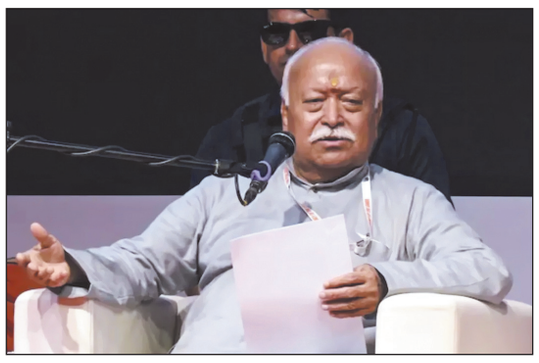

रूढ़िवादी नाराज हैं और उदारवादी उत्साहित। शायद यह भी एक कारण था कि पांच प्रमुख मुस्लिम हस्तियों ने 22 अगस्त 2022 को भागवत से संवाद की को ?शिश में मुलाकात की थी।

यदि उदारवादी समुदाय मोदी सरकार को संतुलित करने के लिए किसी आरएसएस प्रमुख से राहत की उम्मीद करता है तो मतलब हम कुछ आगे बढ़ चुके हैं। इसे आप निराशावादी या आशावादी दृष्टि से देख सकते हैं। यह भी संभव है कि वह सरकार के लिए कठिन समय में पक्ष लेने की भूमिका निभाएं जैसा कि अब जंतर मंतर के बाद हो रहा है। जिस केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, वह भी आरएसएस के एक प्रमुख व्यक्ति हैं।

सबसे पहले हमें देखना होगा कि पिछले गुरुवार को क्या कहा गया। कुछ दिन पहले ही भाजपा की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने जेनज़ी को जेनरेशन गटर या 'गटर पीढ़ी' कहा था। 30 जुलाई को आरएसएस के सह सरकार्यवाह अतुल लिमये ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेनज़ी विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर राष्ट्रविरोधी नारे लगे। उन्होंने कहा कि वामपंथ की 'वैकल्पिक राजनीति' की अवधारणा इस आंदोलन के माध्यम से सफलतापूर्वक परखी गई। उन्होंने कहा कि डॉ. आंबेडकर ने बहुत पहले अराजकतावादियों के बारे में चेतावनी दी थी और अब 'समय है इसे समझने, इसकी व्याख्या करने और ऐसी अराजकतावादी ताकतों से सावधान रहने का, जो राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं।'

भागवत यह सब दूर से देख रहे थे और युवाओं के मोदी सरकार के प्रति गुस्से को लेकर चिंतित थे। यही कारण है कि उन्होंने इंडियाज इंटरनैशनल मूवमेंट टु यूनाइटेड नेशंस (आईआईएमयूएन) का निमंत्रण स्वीकार कर लिया जहां उन्होंने जेनज़ी और जेनअल्फा के साथ सवाल-जवाब का सत्र किया। सबसे पहले उन्होंने जेनज़ी प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रविरोधी कहने वाली आलोचनाओं को खारिज कर दिया।

उन्होंने कहा, 'मुझे जेनज़ी पर विश्वास है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, यह राष्ट्रविरोधी नहीं है।' उन्होंने विस्तार से बताया कि विरोध और आंदोलन सहमति बनाने की प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा हैं। उन्होंने युवाओं की शिकायतों और सुधारों की जरूरत को जायज ठहराया। उन्होंने कहा कि जीडीपी का 6 फीसदी शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। यह सपना 1950 के दशक से चला आ रहा है, लेकिन पीढ़ियों से केवल औपचारिकता बनकर रह गया है। अगर उन्हें पीढ़ियों में से किसी पर विश्वास करना हो तो वे जेनज़ी पर विश्वास करना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलनों को वैध और लोकतांत्रिक संवाद का हिस्सा माना जाना चाहिए, खासकर तब जब सामान्य संचार चैनल विफल हो जाएं।

उन्होंने कहा, 'युवा लोग संवाद पर बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं, आदेश पर नहीं।' उनसे 'बिना सवाल किए आज्ञापालन' की उम्मीद न करें। युवा पीढ़ी का सम्मान करें। कंगना रनौत सबसे पहले इस संदेश को समझ गईं। उन्होंने अपने बयान से पीछे हटते हुए संसद के बाहर पत्रकारों से कहा कि जेनज़ी हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें इस पीढ़ी पर गर्व है।

भागवत ने युवाओं को नेतृत्व का पाठ देते समय एक और महत्त्वपूर्ण और कुछ हद तक दिलचस्प चेतावनी दी। उनसे पूछा गया कि भविष्य के नेताओं के लिए तीन आदर्श गुण कौन से हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नेतृत्व का मतलब टीमवर्क है। जब हम आज किसी नेता के बारे में सोचते हैं, तो एक चित्र उभरता है, सामने खड़े होकर भाषण देना, चुनाव जीतना, लोगों को उपदेश देना। उन्होंने कहा, 'इससे काम नहीं चलता। असली नेता वे होते हैं जो पीछे रहते हैं, भीतर से काम करते हैं। नेतृत्व का मतलब नेताओं को तैयार करना है केवल खुद नेतृत्व करना नहीं।'

स्वाभाविक है कि सवाल उठेगा कि वह किसकी ओर इशारा कर रहे थे, या क्या किसी की ओर इशारा कर भी रहे थे। यह ऐसा प्रश्न है जिसे भाजपा में कोई पूछने या जवाब देने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन यह अनदेखा भी नहीं किया जाएगा।

जंतर मंतर पर सरकार का झुकना नाटकीय और पूर्ण था। यह ठीक उस समय हुआ जब वरिष्ठ मंत्रियों ने कहा था कि वे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की तरह नहीं हैं और उनके मंत्री दबाव में इस्तीफा नहीं देंगे। इस झटके से सरकार मॉनसून सत्र के दौरान ही आहत हुई। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने एक्स पर इंदिरा गांधी का एक पुराना इंटरव्यू साझा किया, जिसमें उन्होंने आपातकाल को सही ठहराया था। विडंबना यह थी कि भाजपा का एक कैबिनेट मंत्री (जबकि भाजपा और आरएसएस के सभी नेता जेल में थे) इंदिरा गांधी का इंटरव्यू साझा कर रहा था जिसमें आपातकाल का बचाव किया गया था। इंदिरा गांधी ने कहा था कि भारत के लिए खतरा आंतरिक और बाहरी दोनों था। उन्होंने कहा कि अगर यह केवल आंतरिक होता और कोई विदेशी हस्तक्षेप नहीं होता तो हम इसे बिना आपातकाल के संभाल सकते थे।

उन्होंने षड्यंत्रों और अराजकता फैलाने की योजनाओं की बात की थी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के घर और संसद को घेरने की धमकी दी थी उन्होंने कहा था, 'हम देखेंगे कि कोई काम नहीं हो सके। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई बाहर न आ सके, कोई अंदर न जा सके।'

इंदिरा गांधी ने कहा कि वे लोग मानते थे कि चूंकि वे चुनावों से नहीं जीत सकते इसलिए वे लड़ाई को सड़कों पर ले जाएंगे। यही लोग लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे। वास्तव में उन्होंने खुद को इतना घिरा हुआ महसूस किया कि अपने सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी भूल करते हुए आपातकाल लागू कर दिया। यह बहस का विषय बना रहेगा लेकिन जो बात निश्चित है वह यह कि उस समय उनके पास कोई और शक्ति, वरिष्ठ सलाहकार, मार्गदर्शक, परिवार का बुजुर्ग या गुरु नहीं था जो उन्हें ऐसे दुस्साहसिक कदम से सावधान करता। भागवत और आरएसएस यह रेखांकित कर रहे हैं कि वे अपनी सरकार के लिए वही खाली जगह भरते हैं। जैसे आरएसएस परिवार के बुजुर्ग या गुरु के रूप में और सरकार शिष्य की तरह हो।

पुराण दिग्दर्शन ....

विश्व विद्या-निरुपणाध्यायः (दशम अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यदि विचार करके देखा जाय तो इसमें भी प्राचीन ऋषियों की अथाह बुद्धि का हो परिचय मिलता है, क्योंकि वर्तमान गवेषकों ने जो परिमाण निकाला है वह (बड़ी दौड़धूप कर के लाखों रुपया व्यय करके और सैकड़ों पुरुषों की जान गवां कर फिर भी अधिकांश अनुमान पर ही स्थिर किया है। और वह भी केवल पृथ्वीतल से ऊपर को उठे हुवे भाग का ही निकाला जा सका है। वर्तमान गवेषकों को अभी तक यह पता नहीं है कि हिमालय पर्वत भूमिगर्भ में कितना धंसा हुआ है, परन्तु त्रिकाल-दर्शी मषियों ने योगबल से अपनी पर्णकुटी में बैठे बैठे अनायास ही ऊपर से लेकर भूगर्भ में धंसे हुवे भाग की चरमसीमा तक के भाग को देखकर पुराणशास्त्रों में स्पष्टतया लिख दिया है। वर्तमान गवेषक हिमालयादि के उस भूगर्भ-प्रविष्ट भाग को न अब तक जान सके हैं और नांही भविष्य में जान सकेंगे ऐसी आशा की जाती है। क्योंकि यह केवल योगीजनों का ही ज्ञातव्य विषय है। अब पाठक विचारें कि ऋषियों की इन अमूल्य सम्मतियों को सरे बाजार कोसने वाले महाशय कहाँ लक न्याय करते हैं। हमें इस पुस्तक का कलेवर भूगोल विषय पर इससे अधिक लिखने की आज्ञा नहीं देता इसलिये पाठक दिङ्?मात्र से ही संतोष करें।

खगोल-बिद्या

पुराण ग्रन्थों में खगोल सम्बन्धी सभी बातों का विवेकपूर्ण एवं निशद विवेचन किया गया है। इसमें सूर्य चन्द्र आदि ग्रह, राहु केतु आदि उपग्रह, नक्षत्र माला, राशिचक्र, आकाश गंगा धूमकेतु, उल्कापिंड, दिग्दाहक पिण्ड, और ध्रुव, गर्ज है कि सभी प्रकार के आकाशचारी अंड और पिंडों का न केवल वर्णनमात्र है, अपितु लौकिकी भाषा में उनकी उत्पत्ति परिवर्तन और गति विगति आदि का रहस्य भी स्पष्ट एवं सरल रीति से प्रतिपादन किया गया है।

क्रमशः ...

भारतीय स्पेश मिशन के जनक कहे जाते हैं विक्रम साराभाई

अनन्या मिश्रा

आज ही के दिन यानी की 12 अगस्त को भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। उनको देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता भी कहा जाता है। विक्रम साराभाई के प्रयासों से ही इसरो की स्थापना हुई थी और वह इसके पहले चेयरमैन बने थे। वह एक प्रतिष्ठित भौगोलिक वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री थे।

गुजरात के अहमदाबाद शहर में 12 अगस्त 1919 को विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी शुरूआती शिक्षा भारत में पूरी की। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सेंट जॉन्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। यहां पर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ली और कॉस्मिक किरण अनुसंधान में अपना योगदान दिया। साल 1942 में विक्रम साराभाई ने मृणालिनी से शादी की थी। जो कि एक निपुण शास्त्रीय डांसर थीं। जिस समय विक्रम साराभाई ने शादी की थी, उस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ऐसे में उनका परिवार विवाह में शामिल नहीं हो पाया था।

डॉ विक्रम साराभाई ने संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत लौटने के बाद नवंबर 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की। शुरूआत में पीआरएल ने अनुसंधान पर ध्यान दिया। लेकिन फिर साराभाई के घर से रिट्रीट की शुरूआत हुई। जिसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नींव रखी थी।

बता दें कि 21 नवंबर 1963 को वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ मिलकर विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में छोटा रॉकेट लॉन्च किया। इसके लिए वह तिरुअनंतपुरम के छोटे से गांव थंबा गए और त्रिवेंद्रम के बिशप को चर्च के अधिग्रहण के लिए मनाया। जिसके बाद इसके विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है। इसके सफल लॉन्च के बाद साराभाई ने घर पर सूचना दी थी।

विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन और भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई थी। यह संस्थान आज भी भारत की प्रगति व उन्नति में अहम भूमिका निभा रहा है। साराभाई के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना भी की थी। साराभाई का यह सपना था कि भारत आत्मनिर्भर बनें और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए। विक्रम साराभाई की इसी सोच ने भारत को अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति बनने में ग्लोबल लेवल पर मदद की। भारत को आजादी के बाद अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में शुरुआत करनी थी। साराभाई ने न सिर्फ राकेट और उपग्रह निर्माण की बुनियाद रखी बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उपग्रह सेवाओं के उपयोग की दशा तथा दिशा तय की। जनवरी 1966 में भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉ. होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने। वह भारत में फार्मास्युटिकल अनुसंधान के क्षेत्र के अग्रणी समर्थक थे। उन्हें साल 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण (मृत्योपरांत) से सम्मानित किया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में 30 दिसंबर 1971 को दिल का दौरा पड़ने से डॉ विक्रम साराभाई का निधन हो गया था।

एशिया में बदल रहा शक्ति संतुलन

जेनिफर कवानाघ

एशिया में दशकों तक अमेरिका की केंद्रीय भूमिका रही है। लेकिन अब चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं ने पूरे सुरक्षा ढांचे को बदलना शुरू कर दिया है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश पहले की तुलना में एक-दूसरे के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसका सीधा संकेत यह है कि एशिया में अब सुरक्षा के नए समीकरण बन रहे हैं। अमेरिका की भूमिका खत्म नहीं हुई है, लेकिन उसके सहयोगी देश अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ज्यादा खुद तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। यह बदलाव केवल सैन्य ताकत का मामला नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में पूरे एशिया के रणनीतिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है।

पिछले कुछ हफ्तों में चीन ने ताइवान के पूर्वी तट तक अपनी समुद्री गश्त का विस्तार किया है। इससे यह संकेत गया है कि जरूरत पड़ने पर वह पूरे ताइवान की समुद्री घेराबंदी करने की क्षमता दिखाना चाहता है। चीन ने जापान पर सैन्य, व्यापार और कूटनीतिक दबाव भी बढ़ाया है। इसके साथ ही उसने पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन की लगातार बढ़ती सैन्य क्षमता ने क्षेत्र के दूसरे देशों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर किया है। यही वजह है कि एशिया में अलग-अलग देशों के बीच रक्षा साझेदारी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है।

जापान ने ऑस्ट्रेलिया, फिलीपीन और भारत के साथ अपने रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। दक्षिण कोरिया के साथ भी रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा चल रही है। इससे जापान की सुरक्षा नीति में आए बदलाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। लंबे समय से रक्षा उपकरणों के निर्यात पर लागू पाबंदियों को खत्म करने के बाद जापान अब दक्षिण कोरिया की तरह क्षेत्रीय हथियार आपूर्तिकर्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव बताता है

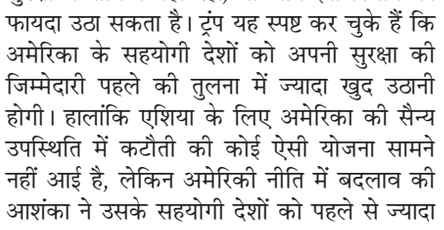

कि जापान अब केवल अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने के बजाय क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है।

ऑस्ट्रेलिया भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जुटा है। उसने प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों के साथ नए समझौते किए हैं। इनमें फिजी के साथ पारस्परिक रक्षा संधि भी शामिल है। दूसरी ओर, जापान, फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग मजबूत हो रहा है। भारत भी इस बदलते क्षेत्रीय समीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन देशों के बीच बढ़ता सहयोग इस बात का संकेत है कि एशिया के देश सुरक्षा की जिम्मेदारी को आपस में बांटने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे एक ऐसी क्षेत्रीय व्यवस्था बनने की संभावना दिखती है, जिसमें किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भरता कम हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद एशिया में अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आशंका यह है कि अगर अमेरिका पहले की तरह क्षेत्रीय सुरक्षा में सक्रिय नहीं रहा, तो चीन इस स्थिति का फायदा उठा सकता है। ट्रंप यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अमेरिका के सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले की तुलना में ज्यादा खुद उठानी होगी। हालांकि एशिया के लिए अमेरिका की सैन्य उपस्थिति में कटौती की कोई ऐसी योजना सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी नीति में बदलाव की आशंका ने उसके सहयोगी देशों को पहले से ज्यादा एकजुट होने के लिए प्रेरित किया है।

अमेरिका पर दुनिया के कई हिस्सों में सैन्य और रणनीतिक जिम्मेदारियां हैं। इन बढ़ते बोझ के कारण उसके लिए पहले की तरह लंबे समय तक एशिया की सुरक्षा का पूरा जिम्मा उठाना आसान नहीं रह गया है। ईरान के साथ हुए युद्ध ने भी अमेरिकी सैन्य शक्ति की सीमाओं को सामने रखा है। इसके बाद अमेरिका को एशिया-प्रशांत क्षेत्र से अपने कुछ सैन्य संसाधन हटाकर दुनिया के दूसरे हिस्सों में लगाने पड़े। ट्रंप की नीति भी यह संकेत देती है कि सहयोगी देशों को अपनी सुरक्षा में ज्यादा योगदान देना होगा। ऐसे में एशिया के देशों के लिए अपनी सामूहिक सुरक्षा क्षमता बढ़ाना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।

अगर बीजिंग को यह लगता है कि अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धता तेजी से कमजोर हो रही है या उसके सहयोगी पहले से ज्यादा असुरक्षित हैं, तो वह इसे अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देख सकता है। यही सबसे बड़ी चिंता है। चीन की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है और वह अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार भी कर रहा है। ऐसे माहौल में अगर क्षेत्रीय देशों को अमेरिकी सुरक्षा छतरी कमजोर होती दिखाई देती है, तो वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने पर और ज्यादा जोर दे सकते हैं। इससे सुरक्षा मजबूत होने के बजाय हथियारों की दौड़ तेज होने का खतरा भी पैदा हो सकता है।

पूर्वी एशिया में सुरक्षा को लेकर चिंता पहले से मौजूद है और अब इसमें हथियारों की होड़ का तत्व भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। जापान ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है। दक्षिण कोरिया में अपने परमाणु हथियार विकसित करने को लेकर बहस तेज है। ऑस्ट्रेलिया परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों और उन्नत मिसाइल प्रणालियों में बड़ा निवेश कर रहा है। वहीं चीन अपनी सैन्य क्षमता और परमाणु शस्त्रागार बढ़ा रहा है। यह स्थिति बताती है कि क्षेत्र के देश केवल कूटनीतिक भरोसे पर निर्भर नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी सैन्य क्षमता को भी सुरक्षा की गारंटी मान रहे हैं।

इतिहास बताता है कि अलग-अलग हितों और अलग-अलग सरकारों वाले एशियाई देश अमेरिका की ज्यादा दखलअंदाजी के बिना भी साझेदारी बना सकते हैं। 1967 में बने 11 सदस्यीय दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान इसका एक उदाहरण है। आसियान को कई बार साझा चुनौतियों पर धीमी और कमजोर प्रतिक्रिया के लिए आलोचना झेलनी पड़ी है। दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने में भी इसकी भूमिका सीमित रही है। इसके बावजूद, इस संगठन ने दशकों तक युद्धों से प्रभावित क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच शांति बनाए रखने में भूमिका निभाई और दक्षिण-पूर्व एशिया तथा चीन के बीच संवाद और सहयोग का एक संस्थागत ढांचा दिया।

सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर ज्यादा संतुलित तरीके से बांटी जाती है, तो इससे एशिया की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के बजाय मजबूत हो सकती है। जापान, फिलीपीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत रक्षा सहयोग सुरक्षा खतरों से निपटने की पहली पंक्ति को मजबूत कर सकता है। जैसे-जैसे अमेरिका के सहयोगी देश खुद ज्यादा सक्षम और आपस में बेहतर तालमेल वाले बनेंगे, वैसे-वैसे उन्हें अपनी सुरक्षा पर होने वाला खर्च भी ज्यादा खुद उठाना होगा। इसका फायदा यह हो सकता है कि किसी संकट के समय अमेरिकी मदद देर से मिले या सीमित रहे, तब भी ये देश मिलकर प्रभावी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में रहें।

इस बदलते सुरक्षा समीकरण में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत उन देशों में है, जिनके साथ जापान ने रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। एशिया में सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा करने की सोच आगे बढ़ती है तो भारत को क्षेत्रीय साझेदारियों में अपनी भूमिका तय करनी होगी। यहां चुनौती केवल सैन्य ताकत बढ़ाने की नहीं है, बल्कि अलग-अलग देशों के साथ भरोसा और समन्वय मजबूत

आज का इतिहास

1602 मुगल बादशाह अकबर के दरबार में मंत्री अबुल फजल को सलीम मिर्जा की शह पर कत्ल कर दिया गया। सलीम ने बाद में जहांगीर के नाम से मुगल सल्तनत संभाली।
1765 इलाहाबाद संधि के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में दखल की शुरुआत।
1831 नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच शांति समझौता।
1833 अमेरिका के शिकागो शहर की स्थापना।
1908 हेनरी फोर्ड की कार कंपनी ने पहला कार मॉडल बनाया।
1914 प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया-हंगरी पर हमले का ऐलान किया।
1914 भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन का जन्म हुआ था।
1919 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म।
1960 नासा ने अपना पहला सफल संचार उपग्रह ईको-ए प्रक्षेपित किया।
1971 सीरिया ने जॉर्डन से राजनयिक संबंध तोड़े।
1981 आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया, जिसकी कीमत 16 हजार डॉलर रखी गई।
1992 उत्तरी अमेरिका के राष्ट्रों- सं.रा. अमेरिका, कनाडा एवं मैक्सिको में मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) सम्पन्न।
2003 संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और इस्त्रायल के बीच फाल्कन सौदे को मंजूरी दी।
2004 फ्रांस के मशहूर स्ट्राइकर जिनेदिन जिदान ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल से सन्यास लिया। इराकी शहर नजफ पर अमेरिकी हमले में 165 मारे गये।
2006 यूरोपीय प्रक्षेपण यान एरियन-5 ने जापान के संचार उपग्रह और फ्रांस के एक सैन्य उपकरण को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया।
2007 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के यान एण्डेवर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुँचे यात्रियों ने स्टेशन पर नई बीम लगाई।
2008 बृज बिहार रेलवे क्रासिंग के निकट खड़ी कालिंदी एक्सप्रेश व पद्मावट एक्सप्रेस में हुए भिड़ंत से नई पाटी घायल हो गयी।
2008 आमिर ख़ान को उनकी फ़िल्म 'तारे ज़मीं पर' के लिए गोलापुड़ी श्रीनिवास मेमोरियल अवार्ड प्रदान किया गया।
2009 भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सी. रंगराजन को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलहाकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने इस पद पर अपनी नियुक्ति के उपरान्त राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

एफसीआरए विधेयक : विदेशी चंदे पर नियंत्रण या संस्थाओं की स्वायत्तता पर नया सवाल?

सत्येंद्र प्रताप सिंह

विदेशी चंदे का मामला भारत में हमेशा संवेदनशील रहा है। सरकार का तर्क है कि विदेशी धन भारत की राजनीति, सामाजिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने का माध्यम नहीं बनना चाहिए। दूसरी तरफ हजारों सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक और जनकल्याणकारी संस्थाएं विदेशी सहयोग के जरिए वर्षों से काम कर रही हैं।

इसीलिए जब विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2026 संसद में आता है, तो बहस सिर्फ विदेशी चंदे की निगरानी तक सीमित नहीं रहती। सवाल यह भी उठता है कि विदेशी फंडिंग लेने वाली संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण कितना हो और उस नियंत्रण की सीमा कहां तक हो।

25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया यह विधेयक अभी लंबित है। सरकार इसे आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष और कुछ प्रभावित संगठनों ने इसके कई प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं।

विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सा उन संस्थाओं की संपत्तियों से जुड़ा है जिनका एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है, संस्था खुद पंजीकरण वापस कर देती है या उसका नवीनीकरण नहीं हो पाता। प्रस्तावित व्यवस्था में ऐसी स्थिति में विदेशी योगदान से जुड़ी संपत्तियों और धन के प्रबंधन के लिए नामित प्राधिकारी की भूमिका तय की गई है।

यहीं से बहस शुरू होती है। मान लीजिए किसी संस्था ने विदेशी सहयोग से वर्षों में स्कूल, अस्पताल, छात्रावास या कोई सामाजिक सेवा केंद्र बनाया। बाद में उसका एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो गया या नवीनीकरण नहीं हुआ। तब उस संपत्ति के भविष्य का फैसला किसके हाथ में होगा?

सरकार कहती है कि ऐसी संपत्तियों को अनिश्चितकाल तक ऐसी संस्था के नियंत्रण में नहीं छोड़ा जा सकता जिसका एफसीआरए दर्जा समाप्त हो चुका है। लेकिन आलोचकों का सवाल है कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई के आधार पर किसी संस्था की वर्षों में बनाई गई संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना उचित प्रक्रिया के पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ किया जाएगा?

इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है। विधेयक को केवल संपत्ति जब्ती के रूप में देखना पूरी तस्वीर नहीं होगी। प्रस्तावित व्यवस्था में संपत्ति के अस्थायी नियंत्रण और उसके बाद की प्रक्रिया का प्रावधान है। कुछ परिस्थितियों में यदि संस्था अपना पंजीकरण बहाल या नवीनीकृत करा लेती है, तो संपत्ति अथवा अप्रयुक्त धन की वापसी की व्यवस्था भी हो सकती है।

लेकिन यहां एक बुनियादी सवाल फिर भी खड़ा होता है-जिस संस्था का प्रमाणपत्र रद्द हुआ है, उसे राहत पाने में कितना समय लगेगा और तब तक उसकी संपत्ति का क्या होगा? किसी संस्था के लिए यह महज कानूनी सवाल नहीं है। उसके पीछे कर्मचारी, लाभार्थी, अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज, स्कूल में पढ़ रहे बच्चे और वर्षों से चल रहे सामाजिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं।

इस बहस में सरकार की चिंता को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं होगा। भारत में विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता का

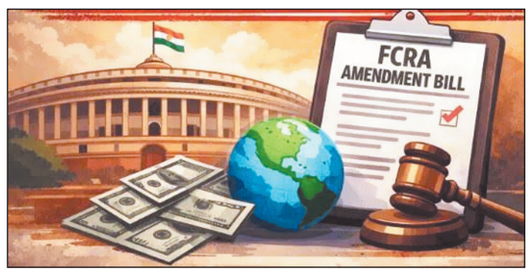

सवाल है। विदेशी धन का इस्तेमाल यदि राजनीतिक गतिविधियों, धार्मिक ध्रुवीकरण, गैरकानूनी गतिविधियों या देश के हितों के विरुद्ध किया जाता है, तो सरकार के पास कार्रवाई का अधिकार होना ही चाहिए।

एफसीआरए का मूल उद्देश्य भी यही है कि विदेशी योगदान का इस्तेमाल पारदर्शी और कानून के अनुरूप हो। समस्या तब पैदा होती है जब नियमन और नियंत्रण के बीच की सीमा धुंधली होने लगे।

सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून का इस्तेमाल केवल वास्तविक उल्लंघन के खिलाफ हो, न कि वैचारिक या प्रशासनिक असहमति रखने वाली संस्थाओं को दबाने के लिए। विधेयक का एक ऐसा पहलू भी है जिसकी चर्चा अपेक्षाकृत कम हो रही है। प्रस्तावित संशोधन में एफसीआरए उल्लंघन के लिए अधिकतम कारावास की सजा को पांच वर्ष से घटाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव है। यानी विधेयक के सभी प्रावधानों को एकतरफा कठोर बताना भी सही तस्वीर नहीं होगी।

एक तरफ सरकार को संपत्तियों के संबंध में ज्यादा प्रशासनिक शक्ति देने का प्रस्ताव है, तो दूसरी तरफ कुछ उल्लंघनों में अधिकतम जेल की सजा कम करने की बात की गई है। इसलिए विधेयक का मूल्यांकन पूरे पैकेज के रूप में करना जरूरी है।

विदेशी सहयोग लेने वाली संस्थाओं में धार्मिक और सामाजिक संगठन भी शामिल हैं। विशेष रूप से कुछ ईसाई संगठनों ने प्रस्तावित बदलावों को लेकर चिंता जताई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद यह मुद्दा और चर्चा में आया। उन्हें कथित तौर पर आश्वासन दिया गया कि नया प्रावधान retrospective यानी पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।

यह आश्वासन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि कानून को पिछली अवधि पर लागू किया जाता, तो पहले से मौजूद संस्थाओं और संपत्तियों पर इसके प्रभाव को लेकर कहीं ज्यादा गंभीर विवाद पैदा हो सकता था। फिर भी भविष्य को लेकर सवाल बाकी है।

यदि किसी संस्था का एफसीआरए प्रमाणपत्र किसी कारण से रद्द होता है तो क्या उसे पर्याप्त समय, सुनवाई और प्रभावी अपील का अधिकार मिलेगा? यही वह सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब कानून में जितना मजबूत होगा, विवाद उतना कम होगा।

विपक्ष का सबसे बड़ा तर्क है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक जल्दबाजी में पारित नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने विधेयक को वापस लेने या संयुक्त संसदीय समिति यानी जीपीसी के पास भेजने की मांग की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी विधेयक पर पुनर्विचार की मांग की है।

जेपीसी की मांग को केवल राजनीतिक विरोध के रूप में देखना भी सही नहीं होगा। जब किसी कानून का प्रभाव हजारों संस्थाओं, करोड़ों रुपये की विदेशी सहायता और उनसे बनी संपत्तियों पर पड़ सकता है, तो व्यापक संसदीय जांच और हितधारकों से बातचीत लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत ही करती है।

सरकार इसे आगे बढ़ाने के मूड में दिखाई देती है। लोकसभा में सरकार के पास पर्याप्त राजनीतिक ताकत होने के कारण वहां विधेयक के आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा है। असल राजनीतिक परीक्षा राज्यसभा में और उससे पहले विधेयक पर होने वाली बहस में होगी। सरकार के सामने दो रास्ते हैं पहला, मौजूदा स्वरूप में विधेयक को तेजी से पारित कराने की कोशिश करना। दूसरा, विपक्ष और प्रभावित संगठनों की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुरक्षा प्रावधानों को और स्पष्ट करना।

दूसरा रास्ता सरकार के लिए जरूरी नहीं कि राजनीतिक कमजोरी का संकेत हो। कई बार संवेदनशील कानूनों में व्यापक चर्चा कानून को अधिक टिकाऊ बनाती है। विदेशी चंदे पर निगरानी जरूरी, लेकिन प्रक्रिया भी निष्पक्ष हो। एफसीआरए के मामले में असली बहस सरकार बनाम एनजीओ नहीं होनी चाहिए। विदेशी धन का इस्तेमाल पारदर्शी होना चाहिए। देश की सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता नहीं हो सकता। किसी संस्था को विदेशी फंडिंग मिलती है तो उसे यह बताना ही होगा कि पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की शक्ति भी कानून और न्यायपूर्ण प्रक्रिया से बंधी होनी चाहिए।

किसी संस्था का पंजीकरण रद्द करना एक प्रशासनिक फैसला हो सकता है, लेकिन उसके परिणाम कई वर्षों के सामाजिक काम पर पड़ सकते हैं। इसलिए कार्रवाई से पहले सुनवाई, स्पष्ट कारण, समयबद्ध अपील और स्वतंत्र समीक्षा जैसी व्यवस्थाएं जितनी मजबूत होंगी, कानून पर भरोसा उतना ही बढ़ेगा।

एफसीआरए संशोधन विधेयक को केवल विदेशी चंदे पर नियंत्रण का कानून समझना शायद इस बहस को छोटा कर देना होगा। असल सवाल यह है कि विदेशी धन पर निगरानी रखते हुए नागरिक समाज की वैधानिक स्वायत्तता कैसे बचाई जाए।

सरकार के पास राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जिम्मेदारी है। संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे विदेशी धन का इस्तेमाल घोषित उद्देश्यों और कानून के मुताबिक करें। लेकिन लोकतंत्र में इन दोनों के बीच एक तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है-निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया।

यदि विधेयक विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाता है, अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करता है और साथ ही निर्दोष संस्थाओं को मनमाने प्रशासनिक फैसलों से सुरक्षा देता है, तो यह कानून व्यवस्था को मजबूत कर सकता है।

लेकिन यदि सरकारी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि किसी संस्था का अस्तित्व और उसकी संपत्ति मुख्यत: प्रशासनिक विवेक पर निर्भर हो जाए, तो फिर सवाल केवल एफसीआरए का नहीं रहेगा। वह सवाल होगा-लोकतंत्र में सरकार की शक्ति की सीमा आखिर कहां तय होती है? और शायद यही इस विधेयक की सबसे बड़ी परीक्षा भी है।

झारखंड का छात्र आंदोलन, सोरेन के निशाने पर भाजपा?

सनत जैन

दिल्ली के छात्र आंदोलन में छात्रों के साथ केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों और दिल्ली पुलिस द्वारा काफी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई थी। जिसमें सैकड़ो छात्र घायल हुए थे। दिल्ली के छात्र आंदोलन को सख्ती के साथ दबाने का प्रयास केन्द्र की भाजपा सरकार ने किया था। आंदोलनकारियों के ऊपर अश्रु गैस, पेलट गन से चली छर्रे वाली गोलियां, लाठी जार्ज इत्यादि का उपयोग किया गया था। जिसकी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया सारे देश में हुई। उसके बाद छात्र आंदोलन सड़कों पर आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने छात्र आंदोलन में राजनीति नहीं हो, इसके लिए राजनीतिक दलों को निशाने पर लिया था। जंतर मंतर के छात्र आंदोलन में जिस तरह की राजनीति भाजपा कर रही थी, लगता है उसका जवाब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शांति के साथ दिया है। जैसे ही झारखंड में छात्र आंदोलन शुरू हुआ। भाजपा इस आंदोलन में सक्रिय हुई। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, उसने झारखंड के छात्र आंदोलन को जिस तरह से कवरेज देना शुरू किया, इससे अंदाजा लग गया था। भाजपा झारखंड के पीछे छुपकर जेन-जी आंदोलन में घुसकर राजनीति करना चाह रही है। उसके निशाने पर हेमंत सोरेन की सरकार थी। इंडिया गठबंधन और हेमंत सोरेन ने भाजपा की इस पदचाप को पहचान लिया है। हेमंत सोरेन ने भाजपा को ही निशाने पर ले लिया, ऐसा अभी तक के हालात को देखते हुए कहा जा सकता है। झारखंड की राजधानी रांची में पिछले 17 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन में उन्होंने बातचीत शुरू की। छात्र नेताओं से बातचीत करके टुकड़े-टुकड़े में मांगे मानी। जांच के लिए तुरंत एक कमेटी बना दी। प्रदर्शनकारियों से बात करके उन्होंने आंदोलन को जारी रहने दिया। आंदोलन समाप्त कराने में हेमंत सोरेन सरकार ने कोई रुचि नहीं ली। सरकार से बातचीत करने के नाम पर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल तीन गुटों में बाट दिया। जिसके कारण छात्रों का यह आंदोलन कमजोर और शांतिपूर्ण रहा। सरकार की सक्रियता के कारण यहां पर भाजपा को आंदोलन से दूर रखा। भाजपा को इस आंदोलन में सोरेन ने घुसने नहीं दिया। जिसके कारण भाजपा को अपने झंडे और डंडे के साथ अलग उपस्थिति दर्ज करानी पड़ी, यही हेमंत सोरेन चाहते थे। भाजपा छात्रों के इस आंदोलन में नहीं घुस पाए। सोरेन समर्थक छात्रों का एक गुट बन गया। दूसरा गुट इंडिया ब्लॉक के साथ में है। छात्र नेता नेहा बोरा छात्रों के आंदोलन में खुलकर भाग ले रही हैं। वह भाजपा और संघ को निशाना बना रही हैं।

छात्रों के इस आंदोलन में एक गुट देवेंद्र महतो का है, दूसरे गुट का नेतृत्व पीयूष कुमार कर रहे हैं। एक गुट का विधायक जयराम महतो नेतृत्व कर रहे हैं। वह अपनी पार्टी के इकलौते विधायक हैं। इन्होंने हाल में ही रिलायंस समूह के परिमल नाथवानी को राज्यसभा के लिए समर्थन दिया था। छात्र आंदोलन में वह किसके लिए काम कर रहे हैं, छात्र आंदोलन में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर सरकार ने मंत्रियों की एक कमेटी बना दी जो आंदोलनकारी छात्रों से लगातार बात करती रही है। सरकार उनकी बात मान रही है, संवाद भी हो रहा है। एक ही मांग पर बात अटकी, वह सीबीआई जांच की मांग।

पीओके को भारत की याद अब आई?

विकास मिश्रा

हमारे बीच ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगते देख कर खुशी होती है। ऐसे लोगों की तो बहुतायत है जो पाकिस्तानी फौज की गोलियों से मरते युवाओं की फोटो देख कर सहानुभूति से भर जाते हैं! और जब ऐसे वीडियो देखते हैं जिनमें पीओके के लोग पाकिस्तानी फौज को चुनौती देते हुए कहते हैं कि वे श्रीनगर और पुंछ वाला रास्ता खोल लेंगे तो हमारे भीतर यह भावना पैदा हो जाती है कि जब वे मिलने को तैयार हैं तो हम पीओके को मुक्त कराने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ते?

मगर मामला इतना आसान है नहीं जितना दिख रहा है। मामला बेहद पेचीदा है। आंदोलन कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी भी कोई दूध की धुली नहीं है। इसके नेता यह कह रहे हैं कि वे श्रीनगर और पुंछ की ओर रास्ता खोलकर जरूरत का सामान मंगवा लेंगे। पीओके के लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डाल कर अपने लिए सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी ने भी भारत सरकार से यह नहीं कहा है कि फौज लेकर आओ और तुम्हारे हक का कश्मीर खुद में मिला लो!

हकीकत यह है कि जिस हिस्से को हम पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहते हैं, वह पूरी कश्मीर घाटी में आतंकवाद का मुख्य द्वार रहा है। पीओके में आज भी डेढ़ सौ से ज्यादा आतंकी समूह सक्रिय हैं। कौन नहीं जानता कि पीओके में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल

मुजाहिदीन और अल-बदर जैसे आतंकी संगठनों का व्यापक ढांचा है।

पीओके में इनके ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। क्या इतने सारे आतंकी समूह बिना स्थानीय लोगों के समर्थन के सक्रिय रह सकते हैं? यह बात भी जगजाहिर हो चुकी है कि पीओके में कम से कम 70 लॉन्च पैड हैं जहां से आतंकियों को भारत के भीतर भेजा जाता है। इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में कहीं न कहीं स्थानीय लोगों का भी हाथ रहता ही होगा!

अब जब पाकिस्तान उनके हकों को मार रहा है। सस्ता अनाज नहीं दे रहा है, बिजली की कमी है, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं तो वे विरोध पर उतरे हैं। उन्हें अब पता चल रहा है कि पाकिस्तानी फौज का इतिहास रहा है कि वह अवाम द्वारा मुखालफत बर्दाश्त नहीं करती और बेइंतहा जुल्म ढाती है। जब गोलियां चल रही हैं तो पीओके के लोगों को भारत की याद आ रही है। मगर इसी बीच यह सच भी वहां के नेताओं ने खुद स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तानी फौज ने उन्हें हथियार दिए थे! तो क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल के लिए दिए? यह खुलासा भी वहां के लोगों ने खुद ही किया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख नेता सरदार अमान खान ने रावलाकोट की एक जनसभा में साफ शब्दों में कहा कि अतीत में पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरियों (उनका आशय पीओके से है) को हथियार दिए और अब वही सेना उन्हें ही आतंकवादी करार दे रही है।

उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी जो हथियार लेकर घूम रहे हैं, वो हथियार उन्हें भारत के खिलाफ लड़ने के लिए दिए गए थे। यानी कश्मीर घाटी को रक्तरंजित करने में उनकी भूमिका रही है। वक्त वाकई बहुत बेरहम होता है। याद कीजिए कि अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ जंग के लिए अमेरिका ने तालिबान को बहुत सारे हथियार दिए थे।

वक्त पलटा तो वही तालिबान अमेरिका के खिलाफ हो गए और अमेरिकियों के हथियारों से ही उनसे लड़ाई लड़ी! पीओके में भी यही मंजर है। पाकिस्तानी फौज के दिए हथियार उसी के खिलाफ काम आ रहे हैं। बड़ी पुरानी कहावत है कि संपोला पालोगे तो एक दिन सांप बन कर तुम्हें ही डसेगा! मगर पाकिस्तान को शायद यह बात अभी भी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है।

यही कारण है कि पीओके में हालात को शांत करने के लिए पाकिस्तान ने जिस शांति समिति का गठन किया था, उसमें जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों को भी शामिल किया गया था। हालांकि पीओके में ऐसे लोगों की संख्या भी काफी है जो यह मानते रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर के उस हिस्से पर जबरन कब्जा कर रखा है।

मगर खुलकर बोलने की हिम्मत कौन करे? यदि किसी ने चूं भी की तो पाकिस्तानी फौज उसे मौत के घाट उतारने में एक मिनट की भी देर नहीं करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो ऑल पार्टीज नेशनल अलायंस के नेता आरिफ शाहिद को माना जा सकता है। उन्होंने न केवल पाकिस्तान की सरजमीं से चलने वाले आतंकवाद और घुसपैठ के लिए पीओके में बने लॉन्चिंग पैड्स का हमेशा विरोध किया था। बल्कि पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान को वे पाकिस्तानी उपनिवेश कहा करते थे। सच बोलने का नतीजा उन्हें 14 मई 2013 को भुगतना पड़ा जब रावलपिंडी में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनके समर्थकों ने हत्या का इल्जाम सीधे पाकिस्तानी फौज और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लगाया। इसका प्रमाण यह भी है कि हत्यारों की खोज के लिए पाकिस्तान की सरकार ने ईमानदारी से कोशिश ही नहीं की। तो चलिए, फिर लौटते हैं इस सवाल पर कि पीओके में जो आग अभी लगी हुई है, उसका क्या होगा? क्या यह आग पाकिस्तान को झुलसा देगी या फिर खुद झुलसकर शांत हो जाएगी? इस संबंध में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है।

बांग्लादेश पर पैनी नजर रख रहा है भारत

नीरज कुमार दुबे

रॉ चीफ पराग जैन के ढाका पहुंचने की खबर सुनते ही पाकिस्तानी आईएसआई के पांव तले जमीन खिसक गयी है। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की बढ़ती सक्रियता और ढाका के सैन्य व खुफिया तंत्र से उसके बढ़ते संपर्क के बीच भारत की खुफिया एजेंसी के प्रमुख का वहां पहुंचना बेहद अहम माना जा रहा है। भले ही इस यात्रा को नियमित सुरक्षा संवाद बताया जा रहा हो, लेकिन इसका समय और मौजूदा क्षेत्रीय हालात इसे खास बना देते हैं। भारत साफ तौर पर बांग्लादेश के बदलते राजनीतिक और सुरक्षा समीकरण पर नजर रख रहा है।

रिपोर्टों के मुताबिक रॉ प्रमुख पराग जैन रविवार को चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ढाका पहुंचे। यह यात्रा बांग्लादेश की खुफिया एजेंसी डीजीएफआई के निमंत्रण पर हुई। सोमवार को जैन ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान के रक्षा मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. एकेएम शम्सुल इस्लाम से मुलाकात की। भारतीय दल ने बांग्लादेश के अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के प्रमुखों और गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद से भी मुलाकात की।

इस दौरे का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पिछले करीब डेढ़ साल में पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया अधिकारियों ने ढाका के चक्कर तेजी से बढ़ाए हैं। जनवरी 2025 में आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक की ढाका यात्रा दशकों बाद किसी पाकिस्तानी खुफिया प्रमुख की ऐसी पहली यात्रा बताई गई थी। इसके बाद बांग्लादेशी सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने रावलपिंडी जाकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर समेत वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों से मुलाकात की। अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के तत्कालीन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी प्रमुख जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के चार दिवसीय ढाका दौरे के बाद पाकिस्तान हाई कमीशन में आईएसआई की एक

विशेष सेल बनाए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई।

इसी बीच, भारत के नए हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी की प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात भी बेहद अहम है। रहमान ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए 'अनुकूल माहौल' बनाने की जरूरत बताई और ढाका ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तेज करने की मांग दोहराई। हालांकि नई दिल्ली ने कहा है कि वह प्रत्यर्पण अनुरोध को कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत देख रहा है।

हम आपको बता दें कि यह मुलाकात ऐसे वक्त हुई जब शेख हसीना ने दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से सार्वजनिक रूप से अपनी पहली बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया दी और दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का दावा किया। उन्होंने 2024 के सत्ता परिवर्तन को सुनियोजित घटनाक्रम बताया तथा अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा और दमन के गंभीर आरोप लगाए। जवाब में ढाका ने शेख हसीना को भारत से ऐसा मंच मिलने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए अपमानजनक बताया। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम एक निजी संस्था ने आयोजित किया था और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इतिहास

इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी रणनीतिक चिंता पाकिस्तान की बढ़ती मौजूदगी है। विशेषज्ञों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईएसआई ने बांग्लादेश में क्षेत्रीय स्तर के कार्यालय जैसी संरचनाएं स्थापित करने की कोशिश की है। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कराची-चटगांव सीधी समुद्री सेवा बहाल हुई, सीधी वाणिज्यिक उड़ानों का रास्ता खुला और राजनयिकों तथा सैन्य अधिकारियों के लिए वीजा-मुक्त व्यवस्था पर सहमति बनी।

भारत के लिए यह इसलिए गंभीर है क्योंकि दोनों देशों के बीच करीब 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा है। यदि बांग्लादेश में कट्टरपंथी या विदेशी खुफिया नेटवर्क गहराई से जड़ें जमाते हैं तो इसका सीधा असर पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, अवैध घुसपैठ, हथियार और आतंकी नेटवर्क पर पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बांग्लादेश को आतंकवादी खतरे के रूप में लेकर कोई सार्वजनिक 'रेड फ्लैग' सामने नहीं आया है।

यहीं रॉ प्रमुख की ढाका यात्रा का सामरिक महत्व सामने आता है। भारत संभवत: बांग्लादेश को किसी एक खेमे में धकेलने की बजाय उसके सुरक्षा तंत्र के साथ प्रत्यक्ष संवाद बनाए रखना चाहता है। देखा जाये तो भारत के लिए बांग्लादेश को नजरअंदाज करना संभव भी नहीं है। भौगोलिक निकटता, व्यापार, कनेक्टिविटी, चिकित्सा सुविधाएं और विकास सहयोग दोनों देशों को एक-दूसरे से जोड़े रखते हैं। दिल्ली बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और बांग्लादेश भारत से विकास सहायता पाने वाला सबसे बड़ा लाभार्थी भी है। लेकिन चुनौती सिर्फ सुरक्षा की नहीं, बांग्लादेश की आंतरिक दिशा की भी है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने सेना और राजनीति में बढ़ते इस्लामी प्रभाव, जमात-ए-इस्लामी की वापसी और पाकिस्तान के साथ बढ़ते संपर्क को लेकर चिंता जताई है। दूसरी ओर, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी उस दौर से गुजर रही है जिसमें शेख हसीना के समय की तेज आर्थिक वृद्धि, मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले नई परिस्थितियां अधिक अनिश्चित दिखाई देती हैं।

नाटो एक साथ कई रणनीतिक और राजनीतिक उलझनों से जूझ रहा

केएस तोमर

नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन) अपने 77 साल के इतिहास के सबसे अहम मोड़ पर खड़ा है। हाल ही में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में सामूहिक सुरक्षा को फिर से मजबूत करने, रक्षा पर ज्यादा खर्च करने का वादा करने और यूक्रेन को लगातार समर्थन देने की बात कहकर संगठन ने अपना भरोसा दिखाया। फिर भी, इस गठबंधन के सामने चुनौती अब सिर्फ रूस से नहीं, बल्कि खुद अमेरिका की राजनीतिक प्रतिबद्धता को लेकर बनी अनिश्चितता से ज्यादा पैदा हो रही है।

नाटो को बार-बार %कागजी शेर% कहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सवाल उठाया है कि क्या वाशिंगटन को यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना जारी रखना चाहिए, अगर सहयोगी यूरोपीय देश सुरक्षा का ज्यादा बोझ उठाने में नाकाम रहते हैं। हालांकि, अमेरिका नाटो का सबसे जरूरी सैन्य आधार बना हुआ है, लेकिन ट्रंप के बार-बार अमेरिकी प्रतिबद्धता को कम करने की चेतावनी ने यूरोप को ऐसे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। हालांकि यह शिखर सम्मेलन सिर्फ यूक्रेन या रक्षा बजट के बारे में नहीं, बल्कि तेजी से बदलती बहुध्रुवीय दुनिया में नाटो की दीर्घकालिक विश्वसनीयता के बारे में था।

आज नाटो एक साथ कई रणनीतिक, राजनीतिक और तकनीकी चुनौतियों से जूझ रहा है। पहली चुनौती गठबंधन की एकता बनाए रखना है। जहां पूर्वी यूरोप के सदस्य देश रूस को सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, वहीं दक्षिणी यूरोप के कई देशों की प्राथमिकता अवैध प्रवासन, आतंकवाद और उत्तरी अफ्रीका की अस्थिरता है। दूसरी चुनौती जिम्मेदारी बांटने को लेकर है। दशकों से, अमेरिकी सरकारों का कहना है कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना पर अत्यधिक निर्भर है। हालांकि, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद कई देशों ने रक्षा खर्च में काफी बढ़ोतरी की है, पर अब भी काफी अंतर बना हुआ है। तीसरी चुनौती यूक्रेन को लंबे समय तक समर्थन जारी रखना है। चौथी चुनौती तकनीकी प्रतिस्पर्धा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वॉरफेयर, अंतरिक्ष सुरक्षा, हाइपरसोनिक हथियार और क्वांटम टेक्नोलॉजी तेजी से सैन्य रणनीतियों को बदल रही हैं। पांचवीं चुनौती सदस्य देशों के भीतर ही राजनीतिक अनिश्चितता है। बढ़ता राष्ट्रवाद, आर्थिक दबाव, सरकारों का बदलना और विदेशों में सैन्य गतिविधियों को लेकर जनता का बढ़ता संदेह समय के साथ गठबंधन की एकता को कमजोर कर सकता है।

नाटो के बदलते स्वरूप से भारत के सामने नए अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। भारत ने हमेशा अपनी रणनीतिक आजादी बनाए रखी है और औपचारिक सैन्य गठबंधनों का हिस्सा बनने से बचा है। आज के बंटे हुए भू-राजनैतिक माहौल में भी यह नीति सही साबित होती है। हालांकि, नई दिल्ली को ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना होगा, जहां अमेरिका का रणनीतिक ध्यान यूरोप और हिंद-प्रशांत के बीच बंटता रहता है। भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता किए बिना अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय ताकतों के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करते रहना चाहिए। रक्षा विनिर्माण बढ़ाना, रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनना, समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और खुफिया सहयोग बढ़ाना भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं होनी चाहिए। साथ ही, उसे रूस के साथ बातचीत के स्थिर रास्ते बनाए रखने होंगे और चीन के साथ तेजी से जटिल होते अपने रिश्तों को भी संभालना होगा। हालांकि, नाटो मुख्यत: यूरो-अटलांटिक गठबंधन है, लेकिन इसके निर्णय हिंद-प्रशांत क्षेत्र को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

करोड़ों की ठगी में कुख्यात तस्कर सुमता विश्नोई गिरफ्तार

नईदिल्ली। चित्तौड़गढ़ के व्यापारी से 2 करोड़ 45 लाख रुपये की ठगी के मामले में गिरफ्तार कुख्यात तस्कर सुमता विश्नोई को पकड़ना पुलिस के लिए आसान नहीं था. पुलिस को जब उसके घर में छिपे होने की सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य नजर आया. घर के बाहर कुत्ते छोड़े गए थे और अंदर से कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी. पुलिस को शक हुआ कि सुमता घर के अंदर ही हो सकती है.पुलिस ने सुथार को बुलाया और लकड़ी का दरवाजा तुड़वाया. दरवाजा टूटते ही पुलिस के सामने कमरे में सुमता विश्नोई अपने एक बेटे के साथ मौजूद मिली. जय हिंद साहब. पुलिस ने दूसरे बेटे तक पहुंचने के लिए कमरे के दरवाजे तोड़ने की तैयारी की तो सुमता ने पुलिस से कहा कि दरवाजा मत तोड़िए, मैं उसे बाहर निकालती हूं. इसके बाद पुलिस ने सुमता विश्नोई और उसके दोनों बेटों विनोद विश्नोई और मनीष विश्नोई को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. अब तीनों को कोर्ट में पेश किया गया।

विदेश जा सकेंगे अभिषेक, सुको ने रद्द किया हाईकोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को हटा दिया, जिसमें विदेश जाने पर लगी रोक में राहत देने से इनकार किया गया था. यह आदेश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने दिया. अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें विदेश जाने की अनुमति देने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी.5 अगस्त को हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सांसद कोलकाता के सरकारी अस्पताल में मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी हेल्थ स्थिति की जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे. हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर टीएमसी नेता मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते, तो विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय के आधार पर यह देखा जा सकता था।

यूपी के मदरसों में फहराया जाएगा तिरंगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत देशभक्ति और राष्ट्रप्रेम से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण को इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए हैं. यूपी में यह अभियान 9 अगस्त से 17 अगस्त 2026 तक चलाया जा रहा है. राज्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि अभियान से प्रदेश के मदरसों और उनमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को व्यापक रूप से जोड़ा जाए. इसके तहत मदरसों में तिरंगा यात्रा, राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं. साथ ही विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है. निर्देशों के मुताबिक, मदरसों में भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी. इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर परिचर्चा कराने को कहा गया है. पत्र में स्पष्ट किया गया है कि इन कार्यक्रमों के अलावा अन्य उपयुक्त देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।

जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते गिरफ्तार

नईदिल्ली। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के विवादित पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले 3 अगस्त को सीआईडी ने उनसे करीब 7 घंटे पूछताछ की थी. यह पूछताछ जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में हुई थी. इसी दौरान राज्यभर में 18 जगहों पर छापेमारी भी की गई थी. 22 जुलाई 2026 को सीआईडी की छापेमारी के बाद खियांग्ते ने इस्तीफा दिया था. उन्होंने कहा था कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए वे पद छोड़ रहे हैं. खियांग्ते पर जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए पहले से ब्लैकलिस्टेड कंपनी टीडीपीएल को चुनने का आरोप है. प्रदर्शनकारी छात्र टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं. रविवार को जेपीएससी के तीन सदस्यों ने भी इस्तीफा दिया था।

कोलंबिया में 6.8 तीव्रता के भूकंप, 77 मरे

नई दिल्ली। कोलंबिया में सोमवार को 6.8 तीव्रता के तेज भूकंप से कई शहरों में धरती हिल गई. भूकंप के झटके मेडेलिन, बोगोटा और कैली समेत कई इलाकों में महसूस किए गए. मेडेलिन में एहतियात के तौर पर कुछ इमारतों और सार्वजनिक जगहों को खाली कराया गया है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र देश के पश्चिमी हिस्से में चोको इलाके के सैन जोस डेल पालमार के पास था. रात बारह बजे तक इस त्रासदी में 77 लोगों की जान जा चुकी थी. बताया जा रहा है कि तेज झटकों के बाद कई जगहों पर लोग इमारतों से बाहर निकल आए. बोगोटा और कैली में भी लोगों ने भूकंप महसूस होने की जानकारी दी. प्रभावित इलाकों में नुकसान की जांच की जा रही है. भूकंप की गहराई करीब 82 किलोमीटर बताई गई. 6.8 तीव्रता का भूकंप काफी मजबूत माना जाता है. ऐसे भूकंप से इमारतों और दूसरी संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि नुकसान कितना होगा, यह भूकंप की गहराई, उसके केंद्र से दूरी और इलाके में बनी इमारतों की मजबूती जैसी चीजों पर निर्भर करता है।

राहुल गांधी भागें नहीं, झारखंड बर्बरता पर दें जवाब : भाजपा

नईदिल्ली। मंगलवार को एनडीए सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं और झारखंड तथा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई पर बहस से बच रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान जारी हंगामे के बीच, विपक्ष ने 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शनों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की है।

इसके जवाब में, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संसद में बने रहने और बर्बरता के आरोपों का जवाब देने को कहा। प्रदर्शन के दौरान

पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह जी जवाब देंगे। राहुल गांधी, भागिए मत। राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए। झारखंड में छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर जवाब दीजिए। एनडीए सांसदों ने पोस्टर दिखाकर राहुल गांधी से झारखंड में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के बारे में जवाब मांगा।

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष की चुप्पी की आलोचना करते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस ने झारखंड में लाठीचार्ज किया और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, उस पर आज वे चुप क्यों हैं? यहाँ अफरातफरी मची है। आज अपनी चुप्पी से वे देश के सामने बेनकाब हो रहे हैं। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने भी राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज होता है, तो राहुल गांधी चुप रहते हैं। उनकी चुप्पी के पीछे क्या वजह है? हम उनसे जवाब की मांग करते हैं।

भाजपा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर सदन को बंधक बनाने और किसी भी तरह की चर्चा न होने देने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बहस के लिए सरकार की तत्परता बताते हुए कहा कि यह संसद का बहुत महत्वपूर्ण सत्र है और सरकार लगातार कह रही है कि वह चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने पेपर लीक से निपटने के लिए एक नया सख्त कानून बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री भी सदन में बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका (विपक्ष का) एकमात्र मकसद हंगामा करना है।

जनहित के मुद्दों से ध्यान भटका रही भाजपा-कांग्रेस : मायावती

लखनऊ। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को बीजेपी और विपक्षी पार्टियों की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पार्टियां मॉनसून सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही में बाधा डाल रही हैं ताकि केंद्र और राज्य सरकारों की कमियों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी देश के युवाओं, यानी जेन-जी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि उनका विरोध सीधे तौर पर छात्रों और उनके माता-पिता की समस्याओं से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि बसपा इन मुद्दों का समाधान खोजने की पूरी कोशिश कर रही है।

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा जैसा कि सभी जानते हैं, कुछ समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष (भाजपा, कांग्रेस और अन्य) किसी न किसी मुद्दे पर संसद में बाधा डाल रहे हैं और जनहित के अहम मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। हो सकता है कि केंद्र और राज्यों में अपनी सरकारों की कमियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए उनके बीच कोई अंदरूनी समझौता हो, या फिर इन मुद्दों पर बात करने से बचने के लिए कोई साजिश हो। देश के लोग साफ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब देश के युवा, यानी जेन-जी, अपनी कई समस्याओं को लेकर बहुत परेशान और चिंतित हैं। बसपा हमेशा से अपनी राजनीतिक सोच के तहत उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। उनका विरोध छात्रों और उनके माता-पिता की समस्याओं से जुड़ा है।

मंगल मिलन में एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का तिरंगे के साथ किया स्वागत

नईदिल्ली। मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में सत्ताधारी गठबंधन की साप्ताहिक संसदीय दल की बैठक के लिए पहुँचे, तो एनडीए सांसदों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ और वंदे मातरम व भारत माता की जय के नारों के साथ उनका स्वागत किया। मंगल मिलन नाम की यह बैठक संसद पुस्तकालय के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, एनडीए नेता और सहयोगी दलों के सांसद शामिल हुए।

वहाँ मौजूद लोगों में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान और एस जयशंकर शामिल थे। एनडीए सहयोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों में जेडी (एस) के एचडी कुमारस्वामी,

टीडीपी के किंजरापु राम मोहन नायडू, आरएसपी-ए के रामदास बंडू अठावले, एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और एनसीपीआई की शताब्दी रॉय शामिल थे।

संसद सत्र के दौरान हर मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक होती है। 20 जुलाई को शुरू हुआ मॉनसून सत्र 13 अगस्त को खत्म होने वाला है। इस सत्र में बार-बार कार्यवाही स्थगित हुई और कामकाज में रुकावटें आईं, जिससे विधायी कामकाज बहुत कम हो पाया। संसद ने पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अमेंडमेंट बिल, 2026 और चार अन्य बिल बिना किसी खास बहस के पास कर दिए। विपक्ष के लगातार विरोध के बीच लोकसभा ने तीन और बिल पास किए।

विपक्ष ने शुरुआत में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया और अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में हेराफेरी का आरोप लगाया। बाद में उन्होंने नीट मुद्दे पर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर चर्चा की मांग की, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी और उनके बयानों की भी मांग की।

संसद में विपक्ष अपना रुख नहीं बदलेगा : खड़गे

नईदिल्ली। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में गतिरोध जारी रहने के बावजूद विपक्ष अपनी मांगों पर शुरू से ही अडिग रहा है और उसने अपना लक्ष्य नहीं बदला है। खड़गे ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई, जिसमें पैलेट गन का इस्तेमाल भी शामिल है, पर बयान दें। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा 18 दिनों से अनसुलझा है।

खड़गे ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि हम अपना रुख नहीं बदल रहे हैं। शुरू से ही हमारा स्टैंड एक जैसा रहा है और हमारे तीन खास मुद्दे हैं। पहला मुद्दा छात्रों पर लाठीचार्ज और फायरिंग का है - हम जानना चाहते हैं कि आदेश किसने दिए और यह सब कैसे हुआ; हम इस बारे में सदन में बयान चाहते हैं। दूसरा, लाठीचार्ज की वजह से कई छात्र बीमार पड़ गए या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा; 100 से ज़्यादा छात्रों को मामूली

चोटें आईं और कई छात्र पैलेट गन से घायल हुए। हम इस मामले पर भी बयान चाहते हैं। 18 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बयान देने की कोई इच्छा नहीं दिखाई जा रही है।

कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि वे बस जल्दबाजी में अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं; यही उनका मकसद है। दूसरा मुद्दा %चंदा चोरी% का है और तीसरा मुद्दा माफ़ी मांगने की मांग है। ये तीनों मुद्दे शुरू से ही उठाए गए हैं, अभी भी अहम हैं और जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता, तब तक ये बने रहेंगे। खड़गे ने कहा कि झारखंड में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन एक अलग मुद्दा है और सवाल उठाया कि क्या सभी मामलों पर एक साथ चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह एक अलग मुद्दा है। सैकड़ों मुद्दे हैं, उन पर अलग-अलग चर्चा होती है? क्या हम हर मुद्दे को एक ही दिन उठाते हैं?

उनकी यह टिप्पणी उस घटना के एक दिन बाद आई है जब उन्होंने और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में जारी गतिरोध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को जिम्मेदार ठहराया था। सरकार के यह कहने के बाद कि गृह मंत्री छात्रों के विरोध-प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई पर बहस का जवाब देने के लिए तैयार हैं, गांधी ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि शाह यह साफ़ करें कि क्या उन्होंने विरोध कर रहे छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था, न कि वे आम विषयों पर बयान दें।

खेल
प्रमुख समाचार

दलीप ट्रॉफी की तैयारी में जुटे वैभव सूर्यवंशी

नई दिल्ली। युवा भारतीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने नए घरेलू सीजन से पहले जिम्बाब्वे के सफल दौरे के बाद नेट्स में जमकर पसीना बहाया। सूर्यवंशी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर प्रैक्टिस करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया। गेंदबाजों पर हावी रहने वाले सूर्यवंशी प्रैक्टिस के दौरान डिफेंसिव और अटैकिंग दोनों तरह के अप्रोच पर ध्यान दिया जोकि बड़े बदलाव की तरह है। सूर्यवंशी की पोस्ट के कैप्शन में लिखा था, तैयारी।

सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे के दौरान 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया था, लेकिन वहां खेली गई तीन पारियों में वे 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। भारत यह सीरीज 1-4 से हार गया था। उनका जिम्बाब्वे दौरा काफी बेहतर रहा जिसमें उन्होंने तीन पारियों में 151 रन बनाकर रन-चार्ट में टॉप किया। इसमें 50.33 की औसत और 196.10 की स्ट्राइक रेट से दो फिफ्टी (जिसमें 81 रन की पारी भी शामिल थी) लगाईं। उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड मिला, क्योंकि भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड से हारने के बाद नए टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में अपनी पहली सीरीज जीती। सूर्यवंशी ने 6 टी20 मैचों में 32.16 की औसत और 189.21 की स्ट्राइक रेट से 193 रन बनाए हैं, जिसमें दो फिफ्टी शामिल हैं। मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 के दौरान सूर्यवंशी ने 15 साल और 99 दिन की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया। वे भारत के सबसे युवा इंटरनेशनल क्रिकेटर बन गए और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का लंबे समय से चला आ रहा रिकॉर्ड (टेस्ट डेब्यू 16 साल 205 दिन; वनडे 16 साल 238 दिन) तोड़ दिया। दलीप ट्रॉफी की बात करें तो ईस्ट जोन के सेलेक्टर्स ने विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को 2026-27 घरेलू सीजन के लिए कप्तानी सौंपी है, जबकि युवा बैटिंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 388 अंक लुढ़का निफ्टी 24,472 पर बंद

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन तेज गिरावट दर्ज की गई। बेंचमार्क इंडेक्स मंगलवार को लाल निशान में बंद हुए। बीएसई का सेंसेक्स 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 112 अंक फिसलकर 24,471 पर बंद हुआ। हालांकि, ब्रॉडर मार्केट में 11 अगस्त को सुस्ती देखने को मिली। घरेलू बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली रियल्टी और मेटल सेक्टर में दर्ज की गई। निफ्टी में टाटा कंज्यूमर, मैक्स हेल्थ समेत नेस्ले इंडिया के शेयर 2-2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ टॉपर लूजर्स रहे। जबकि डॉ रेड्डीज और जोमैटो के शेयरों में ढाई से 4 फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई। ब्रॉडर मार्केट में सुस्ती रही। हालांकि, आईटी और फार्मा सेक्टर में जोश से बिकवाली सीमित रही। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स और स्मॉलकैप इंडेक्स सपाट क्लोज हुए।

चीनी की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बड़ा कदम

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। कई जगहों पर भाव 50 रुपए प्रति किलोग्राम को पार कर गया है। त्योहारों के सीजन में बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। सरकारी और चीनी उद्योग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सरकार एथेनॉल उत्पादन में गन्ने के इस्तेमाल को सीमित करने पर विचार कर रही है। पिछले एक महीने में चीनी के दाम करीब 10 फीसदी बढ़ चुके हैं। त्योहारी सीजन में खपत बढ़ने से अगले तीन महीनों तक कीमतें ऊंची बनी रहने की आशंका है। वहीं, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में कम बारिश के चलते अगले सीजन में चीनी उत्पादन प्रभावित होने का अनुमान है। चालू सीजन यानी सितंबर के अंत तक चीनी मिलों ने करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी एथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्ट किया है।

जुलाई में इक्विटी फंड्स में निवेश 15 प्रतिशत घटा

नईदिल्ली। म्युचुअल फंड इंडस्ट्री में जुलाई के दौरान निवेशकों ने लार्जकैप फंड्स से बड़े पैमाने पर पैसे निकाले। हालांकि, मिडकैप और स्मालकैप का जलवा बरकरार रहा और इन दोनों ही कैटेगरी में ताबड़तोड़ निवेश जारी रहा। खास बात यह रही कि जुलाई में इक्विटी फंड्स में जून के मुकाबले 15 फीसदी इनफ्लो घटा है, इसके बावजूद एसआईपी पर निवेशकों का भरोसा बरकरार रहा और इसमें मासिक आधार 180 करोड़ रुपये ज्यादा पैसा आया है। बाजार में जारी अंडर परफॉर्मेंस का असर साफतौर पर इक्विटी फंड्स इन्फ्लो पर दिख रहा है। एएमएफआई डेटा के मुताबिक, म्युचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल असेट अंडर मैनेजमेंट अब 85.75 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया जो जून के अंत में 82.22 लाख करोड़ रुपये था। इस तरह इंडस्ट्री के असेट्स में 3.53 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है।

ललिता ज्वेलरी मार्ट का आईपीओ 17 को खुलेगा

नई दिल्ली। आभूषण खुदरा कंपनी ललिता ज्वेलरी मार्ट लिमिटेड का 1,700 करोड़ रुपए का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 17 अगस्त को निवेशकों के लिए खुलेगा। कंपनी इस निर्गम से जुटाई गई राशि का उपयोग अपने स्टोर नेटवर्क के विस्तार में करेगी। कंपनी ने आईपीओ के लिए 190-201 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। ऊपरी मूल्य स्तर पर कंपनी का मूल्यांकन करीब 11,250 करोड़ रुपए बैठता है। आईपीओ में 1,200 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 500 करोड़ रुपए तक के शेयर बिक्री पेशकश के जरिए बेचे जाएंगे। नए शेयर जारी कर जुटाई गई राशि का मुख्य रूप से नए स्टोर खोलने में उपयोग किया जाएगा। आईपीओ 19 अगस्त को बंद होगा, जबकि एंकर निवेशकों के लिए बोली 14 को खुलेगी।

अंतरिक्ष में भीड़ : एआई हर सैटेलाइट की खराबी नहीं रोक सकता

टोनी जॉन

पृथ्वी की कक्षा में भीड़ बढ़ रही है। अभी हमारे ग्रह (पृथ्वी) के चारों ओर लगभग 16,000 सैटेलाइट (उपग्रह) घूम रहे हैं, जो जीपीएस नेविगेशन और मौसम की भविष्यवाणी से लेकर बैंकिंग, इमरजेंसी सेवाओं और इंटरनेट संचार तक, हर चीज में मदद करते हैं। हर कुछ हफ्तों में कई नए सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार, इस दशक के भीतर सैटेलाइट की कुल संख्या 1,00,000 से अधिक हो सकती है, जबकि कुछ के मुताबिक, 2030 तक इनकी संख्या 60,000 तक पहुंच सकती है। उपग्रहों की संख्या में इस तीव्र वृद्धि से एक गंभीर चुनौती उत्पन्न हो रही है। हम कक्षीय वातावरण को सुरक्षित रूप से कैसे प्रबंधित करें, साथ ही यह कैसे सुनिश्चित करें कि जिन उपग्रहों पर हम निर्भर हैं, वे विश्वसनीय रूप से काम करते रहें?

आसमान में बड़ी संख्या में सैटेलाइट होने से प्रकाश प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसकी वजह से खगोल विज्ञान व रात के आसमान से जुड़ी गतिविधियों में रुकावटें आती हैं। अधिक उपग्रह का मतलब है अंतरिक्ष में ज्यादा ट्रैफिक, उपग्रहों के आपस में टकराने की ज्यादा आशंका और मलबे का बढ़ता ढेर। सबसे खराब स्थिति में, अंतरिक्ष का कचरा आपस में टकराकर ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है, जिसे रोकना मुश्किल हो जाए। इसे 'केसलर सिंड्रोम' कहा जाता है। इससे पृथ्वी के चारों ओर कचरे का एक बादल बन जाएगा और इसकी कक्षा (ऑर्बिट) बेकार हो जाएगी, जिससे उपग्रह या कोई भी दूसरा अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इससे कम गंभीर स्थिति में, पुराने या खराब हो चुके उपग्रह खतरा बन सकते हैं, अगर वे काम करना बंद कर दें, दूसरी चीजों से टकरा जाएं, या

आखिर में बिना किसी नियंत्रण के वायुमंडल में वापस आ जाएं। सवाल यह है कि जब उपग्रहों को मरम्मत के लिए आसानी से धरती पर नहीं लाया जा सकता, तो धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर मौजूद हजारों उपग्रहों की देखभाल और मरम्मत कैसे की जाएगी?

इस साल मार्च में उपग्रहों के रखरखाव की चुनौती तब और साफ तौर पर सामने आई, जब नासा का एक बड़ा सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से दाखिल हुआ। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने पुष्टि की कि अंतरिक्ष यान पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर दोबारा वायुमंडल में दाखिल हुआ। नासा को उम्मीद थी कि इसके कुछ हिस्से भले ही बच गए हों, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जलकर नष्ट हो जाएगा। इस घटना ने दुनियाभर का ध्यान खींचा, क्योंकि विशेषज्ञों ने इसके नीचे आने की प्रक्रिया पर नजर रखी और अंदाजा लगाया कि इसका मलबा कहां गिर सकता है। साथ ही, इस संभावना पर भी चर्चा हुई कि बड़े मलबे के गिरने से भविष्य में आबादी वाले इलाकों को नुकसान पहुंच सकता है। यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि उपग्रह हमेशा चलते नहीं रहते और किसी भी मशीन की तरह, वे भी पुराने होते हैं। उनमें लगी बैटरियां खराब होने लगती हैं, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे घिस जाते हैं और अंतरिक्ष के कठोर हालात धीरे-धीरे उन पर असर डालते हैं। हालांकि, हवाई जहाज या कारों के विपरीत, हम उपग्रहों को मरम्मत के लिए वर्कशॉप में नहीं ले जा सकते। एक बार लॉन्च होने के बाद, उन्हें तेज रेडिएशन, तापमान में भारी बदलाव और लगातार मैकेनिकल दबाव वाले माहौल में काम करते रहना पड़ता है। सर्विसिंग मिशन तकनीकी रूप से संभव तो है, लेकिन ये महंगे और काफी कम होते हैं। फिलहाल, सैटेलाइट की सेहत की निगरानी मुख्य रूप से जमीन से ही की जाती है। इंजीनियरों को टेलीमेट्री डाटा की लगातार जानकारी मिलती रहती है, जिसमें बैटरी की परफॉर्मेंस, तापमान, बिजली की खपत और ऑनबोर्ड सिस्टम की स्थिति का पता चलता है। वे इस जानकारी का विश्लेषण करते हैं और ऐसे चेतावनी वाले संकेतों की तलाश करते हैं, जिनसे पता चल सके कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। यह तरीका दशकों से बखूबी काम कर रहा है। लेकिन, जैसे-जैसे सैटेलाइट की संख्या दर्जनों से बढ़कर सैकड़ों और हजारों होगी, यह काम और मुश्किल होता जाएगा।

नक्सल मुक्त बस्तर में निकली तिरंगा यात्रा

डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया 7 करोड़ से बने खेल मैदान का शुभारंभ

बस्तर। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांकेर के मिनी स्टेडियम से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में डिप्टी सीएम अरुण साव भी शामिल हुए। करीब 7 करोड़ के खर्च से ये भव्य मैदान तैयार किया गया है। तिरंगा यात्रा और खेल मैदान के शुभारंभ के मौके पर बड़ी संख्या में स्कूल छात्र और खिलाड़ी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ स्थानीय विधायक आशाराम नेताम भी शामिल हुए। आयोजन के दौरान बच्चों का उत्साह देखने लायक था। बच्चे देशभक्ति गीतों पर झूमते और नाचते नजर आए।

आयोजन में शामिल हो रहे बच्चों ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहने चाहिए। आयोजन में शामिल हो रहे ग्रामीणों ने भी तिरंगा यात्रा के आयोजन की तारीफ की। लोगों ने बताया कि दशकों तक नक्सलवाद का दंश झेलने के बाद इस तरह का आयोजन दिल को सुकून देने वाला है। लोगों ने कहा कि अब बस्तर में शांति आने से विकास के कामों में तेजी आई है, यही बदलते बस्तर की नई पहचान है। तिरंगा यात्रा के दौरान उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कांकेर शहर के मिनी स्टेडियम में 7 करोड़ से अधिक की लागत से निर्मित खेल मैदान का शुभारंभ भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा देश की एकता और अखंडता का संदेश देती है। दशकों तक नक्सलवाद से जूझता रहा बस्तर अब नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है और विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि खेल मैदान के मिलने से क्षेत्र के खिलाड़ियों और बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच मिलेगा। इससे बस्तर की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और युवाओं को नई दिशा मिलेगी। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को भव्य बना दिया। राष्ट्रध्वज के साथ निकली इस यात्रा ने नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र में शांति, विकास और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया।

1.31 करोड़ का घोटाला, समिति प्रबंधक सक्ती से गिरफ्तार

सक्ती। जिले के डभरा ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र पुटीडीह में बड़ी गड़बड़ी सामने आई थी। आरोप था कि धान की बोरियों में मिट्टी मिलाकर शासन को करीब 1।31 करोड़ का चूना लगाया गया। जांच के बाद गड़बड़ी की शिकायत सही पाई गई। जिसके बाद गड़बड़ी के मास्टरमाइंड संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत ओर प्राधिकृत अधिकारी श्याम बाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दर्ज शिकायत के मुताबिक 24/11/2025 को अधिकारियों को जानकारी मिली कि डभरा ब्लॉक के धान खरीदी केंद्र पुटीडीह में धान की बोरियों में मिट्टी मिलाया जा रहा है। जानकारी के बाद देर रात जिला पंचायत सीईओ टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो शिकायत सही पाई गई। जांच हुई तो पता चला कि खरीदी केंद्र से 4200 क्विंटल धान भी गायब है, जिसे पूर्ति करने के लिए धान की बोरियों में मिट्टी मिलाकर भेजने की तैयारी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने एफआईआर कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश पर खरीदी केंद्र प्रभारी प्रकाश महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मगर मामले में शामिल संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत, कंप्यूटर ऑपरेटर द्रोण प्रताप शांडिल्य ओर प्राधिकृत अधिकारी श्याम बाई का नाम शामिल नहीं था। जबकि जांच में ये सभी भी जिम्मेदार थे और इन्हीं की देखरेख में खरीदी का कार्य हो रहा था। जांच के दौरान 29/5/26 को कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला सक्ती से एक ओर पत्र जारी हुआ। जिसमें अन्य दोषी संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत, कंप्यूटर ऑपरेटर द्रोण प्रताप शांडिल्य ओर प्राधिकृत अधिकारी श्याम बाई के विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। आरोप है कि इसके बाद भी पुलिस 2 महीने तक आरोपियों की गिरफ्तारी में लेटलतीफी करती रही। लेकिन जब ऊपर से दबाव बनाया गया तब जाकर दोनों की गिरफ्तारी की गई। आरोपी संस्था प्रबंधक शशिकांत महंत ने 6/8/26 को मानव अधिकार आयोग को एक शिकायत की, जिसमें उसने सक्ती कलेक्टर पर टॉयलेट साफ कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं शिकायत के साथ एक वीडियो भी दिया गया है जिसमें शशिकांत टॉयलेट साफ करता दिख रहा है और कोई उसका वीडियो बना रहा है। प्रथम दृष्टया वीडियो को लेकर सक्ती कलेक्टर से मीडिया ने फोन कर बात की तो उन्होंने बताया कि यह बिल्कुल झूठा आरोप है। शशिकांत महंत पिछले 2 महीनों से अपने किए गए भ्रष्टाचार से बचने के लिए तरह-तरह के प्रयास कर रहा था। मगर मैंने साफ कह दिया था कार्रवाई होकर रहेगी। उसने जो वीडियो बनाया है वो उसका षडयंत्र है। वो कहीं भी जाकर टॉयलेट साफ कर के वीडियो बना सकता है, उसकी हम निगरानी कैसे करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि हमने ऐसा कराया होता तो उसको वीडियो कैसे मिलता।

सेवा सेतु केंद्र से डॉली गंधर की आधार संबंधी समस्या का हुआ समाधान

अम्बिकापुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के शासन में नागरिक सुविधाओं को सुगम और सुलभ बनाने की दिशा में सेवा सेतु केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्र के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न शासकीय सेवाओं से संबंधित समस्याओं के निराकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सेवा सेतु केंद्र में प्राप्त आवेदनों के निराकरण से लोगों को शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लेने में सुविधा मिल रही है। इसी क्रम में अम्बिकापुर की रहने वाली सुश्री डॉली गंधर के आधार कार्ड में नाम संबंधी त्रुटि का निराकरण सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से किया गया। आधार कार्ड में नाम गलत होने के कारण उन्हें बैंक खाता खुलवाने में परेशानी हो रही थी। इसके साथ ही बैंक खाता नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भी समस्या आ रही थी। डॉली गंधर ने अपनी समस्या के निराकरण के लिए सेवा सेतु केंद्र पहुंचकर आवेदन किया। आवेदन के आधार पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए उनके आधार कार्ड में नाम संबंधी त्रुटि को सुधार दिया गया। नाम में सुधार होने के बाद अब उनके लिए बैंक खाता खुलवाने की प्रक्रिया आसान हो गई है तथा छात्रवृत्ति प्राप्त करने में आ रही दस्तावेज संबंधी समस्या भी दूर हो गई है। डॉली गंधर ने बताया कि आधार कार्ड में नाम की त्रुटि के कारण उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। बैंक खाता नहीं बन पाने के कारण छात्रवृत्ति का लाभ भी नहीं मिल पा रहा था। सेवा सेतु केंद्र में आवेदन देने के बाद उनकी समस्या का निराकरण हो गया है। उन्होंने कहा कि अब उनका बैंक खाता खुल जाएगा और छात्रवृत्ति प्राप्त करने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। उन्होंने सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से अपनी समस्या का निराकरण होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इस केंद्र के माध्यम से अन्य नागरिकों की समस्याओं का भी समाधान होगा और उन्हें भी शासकीय सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन से किसानों को मिल रहा संबल

उन्नत मक्का बीज और कृषि आदानों से शुभम दुबे की फसल उत्पादन एवं आय में होगी वृद्धि

अम्बिकापुर । किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने तथा मोटे अनाजों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत किसानों को उन्नत कृषि तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज एवं आवश्यक कृषि आदान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके माध्यम से फसल उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन की इस पहल से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और कृषि आदानों का लाभ मिल रहा है, जिसका सकारात्मक असर खेतों में दिखाई दे रहा है। अम्बिकापुर विकासखंड के कृष्णापुर ग्राम के कृषक शुभम दुबे भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन से लाभान्वित होकर मक्का की बेहतर फसल प्राप्त कर रहे हैं। कृषक शुभम दुबे ने बताया कि उन्होंने लगभग दो एकड़ भूमि में मक्का की खेती की है। कृषि विभाग की ओर से उन्हें मक्का का गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया गया। उन्होंने बताया कि बीज की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण पौधों का विकास बेहतर हुआ और खेत में फसल की स्थिति भी काफी अच्छी है।शुभम दुबे ने बताया कि बीज के साथ खाद उपलब्ध कराए जाने से फसल को आवश्यक पोषण मिला, जिससे पौधों की बढ़वार और फसल की गुणवत्ता में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। इसके साथ ही उन्होंने खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा सुझाई गई दवा का उपयोग किया। इससे खेत में घास-फूस का प्रभावी नियंत्रण हुआ और मक्का की फसल को अच्छी तरह विकसित होने का अवसर मिला। समय पर खरपतवार नियंत्रण होने से फसल की स्थिति बेहतर रही और मक्का की फसल समय पर तैयार होने की ओर अग्रसर है। कृषक शुभम दुबे ने बताया कि उनके खेत में मक्का की फसल अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार हो रही है और उत्पादन को लेकर वे काफी उत्साहित हैं। मक्का की फसल जल्दी तैयार होने से उन्हें बाजार में बेहतर समय पर उपज बेचने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले वे अपने खेत में अन्य सब्जियों की खेती करते थे, लेकिन अपेक्षित उत्पादन और आय प्राप्त नहीं हो पाती थी। मक्का की खेती करने के बाद उन्हें उत्पादन के साथ-साथ आय में भी बेहतर परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद है। इससे खेती के प्रति उनका भरोसा और उत्साह बढ़ा है।

उन्होंने कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए गुणवत्तापूर्ण बीज एवं खाद के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विभाग के सहयोग से उन्हें बेहतर फसल प्राप्त करने में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि मक्का की खेती से उनकी आय में वृद्धि होगी और परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी इसका योगदान मिलेगा।

प्रधानमंत्री जनमन योजना में बनी सड़क में आई दरारें और बने गड्ढे

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर आदिवासी बहुल इलाके भरतपुर में कुछ ही महीने पहले पीएम जनमन योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया गया है। बनाई गई सड़क चिडौला से करीं-बैगापारा को जोड़ती है। निर्माण के चंद महीनों बाद ही सड़क में दरारें और गड्ढे बन गए हैं, इस बात की शिकायत ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई जगह सड़कें धंस गई है, तो कई जगहों पर सड़क के किनारे में कटाव हुआ है। सड़क पर लगी डामर की परत भी तेजी से उखड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरते जाने से सड़क की ये दुर्दशा बनने के कुछ ही महीनों में होने लगी है।

ग्रामीणों के मुताबिक चिडौला से करीं-बैगापारा तक बनाई गई सड़क की लंबाई करीब 4।30 किलोमीटर है। इसके निर्माण पर 233।04 लाख यानी करीब 2।33 करोड़ खर्च हुए हैं। यह सड़क प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। सड़क किनारे लगे शिलापट्ट के अनुसार सड़क निर्माण कार्य 27 फरवरी 2025 को शुरू हुआ था और 13 मार्च 2026 को पूरा किया गया।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार कार्य नहीं कराया गया तो सड़क का क्षतिग्रस्त हिस्सा और बढ़ सकता है। सड़क पर बनी पुलिया के एप्रोच हिस्से में भी उखड़ाव और दरारें दिखाई दे रही हैं। पुलिया के आसपास सड़क के बैठने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बरसात के मौसम में पानी का बहाव बढ़ने पर स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि यह मार्ग क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क खराब होने से आवागमन प्रभावित होने के साथ-साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है। शिलापट्ट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी 12 मार्च 2031 तक संबंधित ठेकेदार की है। इसके लिए करीब 15।95 लाख का प्रावधान किया गया है। ऐसे में सड़क निर्माण के कुछ महीनों बाद ही सामने आई खराबियों के बाद अब निगाहें संबंधित निर्माण एजेंसी और विभागीय निगरानी व्यवस्था पर टिकी है। सड़क पर कई जगह गड्ढे होने की जानकारी मिली है। इस संबंध में पीएमजीएसवाई के संबंधित अधिकारी से चर्चा की गई है और पूरी स्थिति का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। एसडीएम ने कहा कि सड़क खराब होने के पीछे निर्माण में कमी है या कोई भौगोलिक कारण, जांच के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। जो भी कारण सामने आएगा, उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

सरकारी शराब दुकान में चोरी तीन आरोपियों को दबोचा

बिलासपुर। मस्तूरी थाना क्षेत्र के गतौरा स्थित शासकीय कम्पोजिट मदिरा दुकान में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को मस्तूरी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कर्ज में डूबे होने के कारण शराब दुकान में रखी नकदी लूटने की योजना बनाई थी। एसडीओपी सुदीप सरकार ने बताया कि 3 अगस्त की रात करीब साढ़े 3 बजे चार नकाबपोश आरोपी शराब दुकान पहुंचे। उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को चाकू दिखाकर धमकाया और मारपीट कर उनके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और ग्राइंडर कटर एवं छेनी से लॉकर काटने की कोशिश की,लेकिन सफल नहीं हुए। इसके बाद आरोपी शराब की बोतलें, दो मोबाइल फोन और सीसीटीवी का डीवीआर लेकर फरार हो गए। जांच के दौरान पुलिस ने अनिल ध्रुव उर्फ अन्ना, पिंटू निषाद और सुशील निर्मलकर को गिरफ्तार किया।आरोपियों की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, स्कूटी, गैस कटर, छेनी, चाकू लूटे दो मोबाइल बरामद किए गए हैं।

नकली नोट गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा। पुलिस ने नकली नोट बनाने और उन्हें बाजार में खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना बोड़ला, चौकी पोंडी और साइबर थाना पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है।

आरोपियों के कब्जे से करीब 12 लाख 50 हजार रुपये के नकली नोट, कलर प्रिंटर, मोबाइल फोन और टाटा पंच ईवी कार बरामद की गई है। कवर्धा एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि 3।75 लाख रुपये की उधारी चुकाने के नाम पर नकली नोटों की डिलीवरी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकर में आई और इस मामले का खुलासा हुआ। कवर्धा एसपी ने बताया कि प्रार्थी दिनेश कुमार यादव को 9 अगस्त को कथित तौर पर 4।50 लाख रुपये के नकली नोट दिए गए थे। नोटों के नकली होने की जानकारी मिलने के बाद मामले की शिकायत पुलिस से की गई। शिकायत मिलते ही बोड़ला थाना, पोंडी चौकी और साइबर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को सुराग मिले।

पार्सल मंगाकर बिलासपुर में खपा रहा था ओजी गांजा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में गांजा तस्करी का खुलासा हुआ है। आरोपी कोलकाता से पार्सल के जरिए गांजा मंगाकर तस्करी कर रहा था। कोलकाता से पार्सल के जरिए ओरिजनल गैंगस्टर यानि ओजी गांजा मंगाया था। पुलिस ने आरोपी के पास से 5।32 ग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि शहर में बाहर से नशीला पदार्थ मंगाकर सप्लाई किए जाने की सूचना पर जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को शोभित जाजोदिया के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को यह पता चला कि आरोपी पार्सल के जरिए गांजा मंगा रहा है। आरोपी पार्सल पहुंचाने वाले व्यक्ति को इसके लिए एक हजार रुपये देता था।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले वह अपने मामा के घर कोलकाता गया था। इसी दौरान उसने वहां से ह्व गांजा लिया और बाद में पार्सल के माध्यम से इसे बिलासपुर मंगाना शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार आरोपी पार्सल को सीधे बिलासपुर नहीं मंगवाता था, बल्कि रायपुर के पते पर पार्सल मंगवाता था।

प्रमुख सचिव ने विभागीय योजनाओं की ली समीक्षा बैठक

बिलासपुर। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक की. प्रमुख सचिव ने बैठक में कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत दूर दराज के गांवों में रहने वालों को शासन की सुविधाएं देने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। सोनमणि बोरा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी पीवीटीजी की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मल्टीपल सेंटर्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सामुदायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। बैठक के दौरान प्रमुख सचिव बोरा ने छात्र हित में छात्रवृत्ति की स्वीकृति निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने जल्द से जल्द संस्था प्रमुखों की बैठक आयोजित करने को कहा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त तक गांवों के आदि सेवा केंद्रों में आयोजित होने वाली जनसुनवाई की तैयारियों की समीक्षा भी की।

बिलासपुर में तंत्र-मंत्र से जान से मारने की कथित धमकी

बिलासपुर। कथित रुप से तांत्रिक पूजा-पाठ के जरिए जान से मारने की धमकी देने के केस में, तोरवा थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप है कि उन्होने पीड़ित से जमानत के लिए पैसे मांगे लेकिन पीड़ित ने पैसे देने से इंकार कर दिया। जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को डराया धमकाया कि वो तांत्रिक पूजा पाठ के जरिए उसे जान से मार देंगे अगर वो जमानत के पैसे नहीं देता है। पीड़ित की शिकायत पर तोरवा थाना पुलिस ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम की धारा सात के तहत जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर पुलिस के अनुसार, आरोपी ओम बोले का भाई प्रियांशु बोले तोरवा थाने के एक आपराधिक प्रकरण में चालान पेश होने के बाद जेल में था। इसी मामले में जमानत कराने को लेकर ओम बोले और उसके साथियों ने फरियादी से कथित तौर पर गाली-गलौच करते हुए 1 लाख नकद की मांग की। आरोपियों ने कहा कि प्रियांशु का कोर्ट से जमानत कराने में काफी पैसा खर्च हुआ है।

हाथियों का झुंड कन्या छात्रावास परिसर में घुसा, इलाके में मची दहशत

गौरेला पेंड्रा मरवाही। मरवाही वनमंडल इलाके में मध्य प्रदेश से आए हाथियों ने जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। रिहायशी इलाके में हाथियों के पहुंचने से इलाके में दहशत का माहौल है। हाथियों के झुंड ने खेतों में लगी फसलों को रौंद दिया है। स्थानीय किसान अपनी फसलों को लेकर काफी परेशान हैं। हाथियों की दहशत के चलते इलाके के लोग रात को जागते रहे हैं।

हाथियों का झुंड फसलों को रौंदने के बाद मरवाही आईटीआई क्षेत्र में स्थित कन्या छात्रावास परिसर तक पहुंच गए हैं, जिसके बाद प्रशासन और वन विभाग में हड़कंप मच गया है। छात्रावास परिसर में हाथियों की मौजूदगी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां रह रही सभी 58 छात्राओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। रात के समय हाथियों के छात्रावास परिसर में पहुंचने से अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाथियों का झुंड बीते कई दिनों से इलाके में डेरा डाले हुए है। हाथियों के झुंड ने छात्रावास परिसर को भी नुकसान पहुंचाया है।

हास्टल की दीवार को भी हाथियों ने तोड़ दिया है। हॉस्टल के गार्ड ने बताया कि गार्ड रूम की खिड़की को भी हाथियों ने तोड़ डाला है। वन विभाग की टीम एहतियात के तौर पर छात्रावास परिसर के आस पास सुरक्षा घेरा बनाने की कोशिश कर रही है ताकि हाथियों को वहां से दूर रखा जा सके। वन विभाग के मुताबिक हाथियों के झुंड में कुल तीन हाथी हैं लेकिन वो काफी उत्पात मचा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई मकानों को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। हॉस्टल के पास ही एक शासकीय नर्सरी भी है जिसमें हाथियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग के साथ पुलिस की टीम भी क्षेत्र में लगातार मुस्तैद है। ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने और उनके नजदीक नहीं जाने की समझाइश दी जा रही है। इसके बावजूद कई ग्रामीण हाथियों को देखने और उनका वीडियो बनाने के लिए काफी करीब तक पहुंच रहे हैं, जिससे कभी भी गंभीर घटना घट सकती है।

एनएसयूआई के विरोध पर अग्रवाल समाज को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला निरस्त

बिलासपुर। एनएसयूआई के जबरदस्त विरोध के बाद आखिरकार गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर की करीब 5 एकड़ जमीन अग्रवाल समाज को दिए जाने का फैसला निरस्त कर दिया गया है. ह्स्ड्ढ के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने संबंधित निर्णय को निरस्त कर दिया है. गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस फैसले को ह्स्ड्ढ ने छात्रहित में हुई जीत बताते हुए अब पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। ह्स्ड्ढ जिला अध्यक्ष, रंजीत सिंह के नेतृत्व में छात्र प्रतिनिधिमंडल विश्वविद्यालय पहुंचा और अपनी मांगों से विश्वविद्यालय प्रबंधन को अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने विश्वविद्यालय की जमीन को विद्यार्थियों के हित में उपयोग करने की मांग की। एनएसयूआई का कहना है कि विश्वविद्यालय में छात्रावास, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं, नए विभाग और शोध सुविधाओं के विस्तार की जरूरत है। प्रबंधन से मुलाकात के पहले विश्वविद्यालय पहुंचने पर ह्स्ड्ढ कार्यकर्ताओं को मुख्य गेट पर रोक दिया गया। बाद में प्रशासनिक भवन के गेट भी बंद कर दिया गया। इससे परिसर में काफी देर तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही। कार्यकर्ताओं ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी के नहीं पहुंचने पर ह्स्ड्ढ कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक भवन के दोनों गेट तोड़ दिए। स्थिति को देखते हुए अधिष्ठाता छात्र कल्याण मेहता ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन स्वीकार किया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ।

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

हमर छत्तीसगढ़ के पहिली लोक परब

12 अगस्त 2026

हरेली तिहार

के गाड़ा-गाड़ा बधाई

कृषकों का आर्थिक सशक्तीकरण

ढाई वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के खाते में **₹1.50 लाख करोड़** से अधिक अंतरित

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि :
25 लाख से अधिक किसानों को **₹11,277 करोड़** का भुगतान

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना

भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष **₹10,000** की आर्थिक सहायता

कृषि का आधुनिकीकरण

जीएसटी 2.0 लागू होने से **कृषि उपकरण हुए सस्ते**

कृषक उन्नति योजना

₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ **21 क्विंटल** धान खरीदी

फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन

धान के अतिरिक्त अन्य खरीफ फसलों की खेती पर प्रति एकड़ **₹15,000** की आदान सहायता

आसान ऋण सुविधा

खाद- बीज की खरीदी के लिए **ब्याज मुक्त ऋण**

हरियर धरती, खुशहाल किसान
समृद्धि और जनकल्याण, सुशासन की पहचान

संवाद-48731/159

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.